Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-17, अंक-07 01-15 अप्रैल, 2022 (पाक्षिक) ₹20

'परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा'

उत्तराखंड एवं मणिपुर में भाजपा सरकारों ने ली शपथ

कश्मीर फाइल्सः ऐतिहासिक मोड़

ऑपरेशन गंगाः सबसे लंबे निकासी अभियान में से एक

बीरभूम हिंसा : सीबीआई जांच की मांग

मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

आतंकवादी घटनाओं में शहीद हुए जम्मू-कश्मीर के बहादुर पुलिसकर्मियों के परिवारों को जम्मू में नियुक्ति पत्र सौंपते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

सूरत (गुजरात) में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत करते गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और अन्य वरिष्ठ नेतागण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने

उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च, 2022 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। श्री धामी ने उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर कीर्तिमान स्थापित किया है। देहरादून स्थित पैरेड ग्राउंड में...

07 लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने एन. बीरेन सिंह

श्री एन. बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। श्री सिंह ने 21 मार्च को राजभवन...

09 परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 मार्च, 2022 को नई दिल्ली के अम्बेडकर भवन...

26 भारत-जापान के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर

जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ 14वें भारत...

28 गुजरात के लोगों ने सहकारिता का चमत्कार देखा है: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 मार्च को गुजरात के सूरत में सुमुल...

वैचारिकी

लोग, जो हमें प्रेरणा देते हैं / **पं. दीनदयाल उपाध्याय** 14

श्रद्धांजलि

कुशल संगठक सुन्दर सिंह भण्डारी 15

लेख

जनादेश, मतदाता संदेश व राजनीतिक निहितार्थ / **डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे** 16

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास / **लाल सिंह आर्य** 18

कश्मीर फाइल्स: ऐतिहासिक मोड़ / **बैजयंत जय पांडा** 20

हिंसा, बूथ-कैप्चरिंग और उत्पीड़न का शिकार 'बंगाल' / **डॉ. अनिर्बान गांगुली** 21

ऑपरेशन गंगा: भारत के सबसे लंबे निकासी अभियान में से एक / **विजय चौथाईवाले** 23

अन्य

बीरभूम हिंसा : भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग 10

वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 48.4 प्रतिशत बढ़कर 13,63,038 करोड़ रुपये हुआ 11

भारत ने 400 अरब डॉलर का उत्पाद निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किया 12

देश में 12-14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू 13

मीडिया ने योग, फिटनेस और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' को लोकप्रिय बनाने में बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई: नरेन्द्र मोदी 25

आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र' के लिए मेजबान देश समझौते पर किए हस्ताक्षर 30

रक्षा मंत्री ने 'फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटिग्रेशन परिसर' का किया उद्घाटन 33

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

माताओं और बहनों के जीवन को आसान बनाने में जल जीवन मिशन अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है। जन–जन की भागीदारी से घर-घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प पूरा होगा।

जगत प्रकाश नड्डा

हैदराबाद में हुए दर्दनाक अग्निकाण्ड में बिहार के मजदूरों की जान जाने से मन दुःखी है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

अमित शाह

मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में बहुत ही कम समय में बड़ा परिवर्तन आया है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण और लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाकर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने यहां एक सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के युग की शुरुआत की है।

राजनाथ सिंह

भारत माता को ग़ुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके 'बलिदान दिवस' पर मैं स्मरण एवं नमन करता हूं। आजादी के संघर्ष में इन क्रांतिकारियों का त्याग एवं बलिदान भारतवासियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।

बी.एल. संतोष

यह देखकर अच्छा लगा कि कश्मीर फाइल्स देखने वाले दर्शकों की बहुतायत संख्या उन युवा दर्शकों की है जो 20 वर्ष की आयु से कम या उससे अधिक है। ये वे हैं जिन्हें अच्छी तरह से सूचित और सत्य से अवगत होना चाहिए।

नितिन गडकरी

देश में चल रहे विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का विस्तार! 16 मार्च से 12-14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो रहा है और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रिकॉशनरी डोज भी लगनी शुरू होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

संपादकीय

सुशासन, विकास और परफॉर्मेंस का दौर

हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम से यह स्पष्ट है कि भारत की जनता का समर्थन दिनोदिन सुशासन, विकास एवं परफॉर्मेंस की राजनीति के लिए बढ़ रहा है। चार राज्य, जिनमें भाजपा को जनता ने पुनः अपना भारी आशीर्वाद दिया है, यह इंगित करता है कि भाजपा जनाकांक्षाओं को पूरा करने वाली राजनैतिक पार्टी के रूप में उभरी है। जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का ही परिणाम है कि आज भाजपा देश में राजनैतिक स्थिरता का पर्याय बन चुकी है। राजनैतिक अस्थिरता के दशकों का दौर जिसमें किसी दल की सरकार शायद ही कभी पुनः चुनी जाती थी अथवा अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण कर पाती थी, उसके बाद देश की राजनीति स्थिर हो रही है। लगभग तीन दशकों के पश्चात् 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत तथा 2019 के चुनाव में उससे भी बड़ा जनादेश मिलना, देश में हुए राजनैतिक परिवर्तन का द्योतक है। जैसे-जैसे विभिन्न प्रदेशों में हर चुनाव के साथ भाजपा के प्रति जनसमर्थन बढ़ता जा रहा है, राजनैतिक स्थिरता की यह प्रक्रिया और भी अधिक सुदृढ़ होती जा रही है। यह समर्पण, सेवा एवं प्रतिबद्धता की राजनीति की जीत है। यह देशभर में करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के निःस्वार्थ सेवा, 'राष्ट्र प्रथम' के प्रति समर्पित नेतृत्व और 'आत्मनिर्भर भारत' के मंत्र की जीत है।

जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का ही परिणाम है कि आज भाजपा देश में राजनैतिक स्थिरता का पर्याय बन चुकी है

जहां एक ओर देश की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था, शिक्षा जगत, मीडिया, सिनेमा सहित हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। हालिया फिल्म 'कश्मीर फाइल्स' सिनेमा जगत में एक ऐसे परिवर्तन को दर्शाती है जिसमें यदि सच्ची घटनाओं को निर्भीकतापूर्ण दिखाया जाए, तब बिना मार्केटिंग, ब्रांडिंग या पीआर एजेंसियों के भी एक फिल्म सफलता के नए आयाम गढ़ सकती है। जिस प्रकार से इस सिनेमा में कश्मीरी हिंदुओं की दुर्दशा, दिल दहलाने वाला नरसंहार तथा उनका विपरीत परिस्थितियों में पलायन दिखाया गया है, उसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। वास्तविकता यह है कि यह पहली बार है, जब कश्मीरी हिंदुओं की हृदय विदारक व्यथा पर गंभीरता से कोई फिल्म बनाई गई हो तथा देश को उन सच्चाइयों का पता चला जो अब तक लोगों की नजरों से ओझल थी। इस फिल्म से बॉलीवुड के उस वर्ग का चेहरा भी बेनकाब हुआ है जो कश्मीर के विषय पर मनगढ़ंत कहानियों पर सिनेमा बनाकर घाटी में पसरे आतंकवाद-अलगाववाद के पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास करते थे। ऐसे सिनेमा निर्माताओं को अब यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे कपोल-कल्पित कथाओं के आधार पर बनी फिल्मों से घाटी में हिंसा एवं अलगाववाद की मानसिकता पनपी थी। साथ ही, 'कश्मीर फाइल्स' के निर्माता, अभिनेता एवं अन्य सहयोगियों को सच बताने के उनके साहस तथा बॉलीवुड को झूठ की फैक्ट्री की छवि से बाहर निकालने के उनके प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। जिस प्रकार से पूरे देश की जनता ने इस फिल्म का समर्थन किया है तथा अब तक इसे सबसे बड़े 'ब्लॉकबस्टर' बनाने के स्तर पर ले आए हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

आज जबकि आत्मविश्वास से भरे एक ऐसे देश का उदय हो रहा है जिसके मन में 'आत्मनिर्भर भारत' का संकल्प है, हर ओर एक नए प्रकार की ऊर्जा देखी जा सकती है। एक ऐसा भारत जो कोविड-19 वैश्विक महामारी की चुनौतियों का न केवल सफलतापूर्वक सामना करता है, बल्कि अन्य देशों को इस कठिन घड़ी में सहायता भी करता है, एक 'नए भारत' की शक्ति को दर्शाता है। एक भारत जो कोविड-रोधी टीकों का निर्माण कर सकता है, जो हर महामारी में चुनौती को विभिन्न सुधारों के माध्यम से अवसर में बदल सकता है जो 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे सकता है, महामारी में समाज के कमजोर वर्गों की चिंता कर सकता है और हर व्यक्ति को निःशुल्क टीका दे सकता है, यह भारत आज से मात्र सात वर्ष पूर्व यूपीए के कुशासन के दौर में असंभव दिखता था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं करिश्माई नेतृत्व ने करोड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं एवं देशभर में जन-जन को निःस्वार्थ राष्ट्र सेवा के लिए अपने अथक प्रयासों एवं स्वयं के उदाहरण से प्रेरित किया, उसके कारण ही संभव हो पाया है। आज एक ऐसे भारत का उदय हुआ है जो अब किसी क्षेत्र में पिछड़ता नहीं, बल्कि हर कार्य को लक्ष्य कर समय से पहले पूर्ण कर लेता है। आज जब भारत अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान रहा है, 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य अब दूर नहीं। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

शपथ ग्रहण समारोह, उत्तराखंड

पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने

उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी ने 12वें मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च, 2022 को पद और गोपनीयता की शपथ ली। श्री धामी ने उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर कीर्तिमान स्थापित किया है। देहरादून स्थित पैरेड ग्राउंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) श्री गुरमीत सिंह ने श्री धामी के साथ आठ कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। ये हैं— श्री सतपाल महाराज, श्री धन सिंह रावत, श्री सुबोध उनियाल, श्री गणेश जोशी, श्रीमती रेखा आर्य, श्री प्रेमचंद अग्रवाल, श्री सौरभ बहुगुणा और श्री चंदन राम।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी सहित भाजपाशासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण उपस्थित थे।

इससे पूर्व 21 मार्च को नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें श्री पुष्कर सिंह धामी को विधायक दल का नेता चुना गया। इस बैठक में उत्तराखंड में पार्टी द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं सह-पर्यवेक्षक केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी तथा केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री एवं उत्तराखंड चुनाव प्रभारी श्री प्रह्लाद जोशी भी उपस्थित थे।

विदित हो कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी। राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 47 सीटों पर जीत प्राप्त की। प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई।

लगातार दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर कहा, "प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से मुझे पुनः प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में देवभूमि उत्तराखण्ड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा ध्येय प्रदेश की प्रगति और जन आकांक्षाओं की पूर्ति है और मैं अपने इन कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करूंगा।" ■

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ढेरों बधाई। बीते 5 वर्षों में देवभूमि ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि आप और आपके सभी मंत्री उसे और गति प्रदान करेंगे, जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का एक नया प्रतिमान स्थापित करेंगे।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

देहरादून में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के शपथग्रहण समारोह में शामिल हुआ। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में धामी जी देवभूमि के विकास में एक नया प्रतिमान स्थापित करेंगे। नये मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

शपथ ग्रहण समारोह, मणिपुर

लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने एन. बीरेन सिंह

श्री एन. बीरेन सिंह लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। श्री सिंह ने 21 मार्च को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राजधानी इंफाल स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल श्री एल. गणेशन ने श्री एन. बीरेन सिंह को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। साथ ही, पांच मंत्रियों— श्री बिस्वजीत सिंह, श्री वाई खेमचन सिंह, श्री नेम्चा किपगेन, श्री अवंगबोउ नेवमाई एवं श्री गोविंदास कोंथौजम ने मंत्री पद की शपथ ली।

शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं मणिपुर विधानसभा चुनाव प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव, भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं भाजपा मणिपुर प्रदेश प्रभारी श्री संबित पात्रा, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब, नागालैंड के उपमुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन सहित अनेक गणमान्य नेतागण उपस्थित थे।

ध्यातव्य है कि 20 मार्च को भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री एन. बीरेन सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया। इस बैठक में भाजपा द्वारा नियुक्त केन्द्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और सह-पर्यवेक्षक केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजीजू उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, ''यह सभी द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया एक अच्छा निर्णय है। यह सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार हो।'' उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हैं।

विदित हो कि मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 सीट जीतकर भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। 2017 में भी भाजपा ने सरकार बनाई थी और श्री एन. बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने थे।

जीत के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उनके 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' मंत्र ने राज्य के लोगों को बहुत विश्वास दिलाया। ■

श्री एन. बीरेन सिंह जी को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मुझे विश्वास है कि उनकी टीम और वो मणिपुर को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए अच्छे काम को जारी रखेंगे।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में एन. बीरेन सिंह जी और नवनिर्वाचित कैबिनेट के सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मणिपुर नई ऊंचाइयों और समृद्धि की ओर बढ़ेगा, विकास की एक नई सुबह को जन्म देगा।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

जीवन परिचय
एन. बीरेन सिंह

- श्री एन. बीरेन सिंह का जन्म 1 जनवरी, 1961 को मणिपुर की राजधानी इंफाल में हुआ था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मणिपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की।
- उन्होंने शुरुआत में फुटबॉल को अपने करियर के तौर पर चुना। बाद में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भर्ती हो गए। यहां भी उन्होंने अपनी खेल की रुचि को आगे बढ़ाया और घरेलू मुकाबलों में अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे। उन्होंने डूरंड कप जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया।
- फुटबॉल और बीएसएफ में लंबे समय तक सेवा देने के बाद 1992 में वे पत्रकारिता की तरफ उन्मुख हुए और उन्होंने मणिपुर के ही स्थानीय अखबार नाहरोल्गी थोउदांग में नौकरी शुरू की।
- पत्रकारिता में भी वे काफी तेजी से आगे बढ़े और 2001 तक वे अखबार में संपादक के पद तक पहुंच गए।
- इसके बाद वे राजनीति में सक्रिय हो गए। 17 अक्टूबर, 2016 को वे भाजपा में शामिल हुए। वे मणिपुर भाजपा के प्रवक्ता एवं चुनाव प्रबंधन समिति के सह संयोजक बने।
- 2017 के विधानसभा चुनाव में वह हेनगांग सीट से चुनाव जीते और 15 मार्च, 2017 को पहली बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने।

जीवन परिचय
पुष्कर सिंह धामी

- 16 सितंबर, 1975 को पिथौरागढ़ में जन्मे श्री पुष्कर सिंह धामी की मां का नाम श्रीमती विशना धामी और पिता का नाम श्री शेर सिंह धामी है।
- उनके पिता सेना के एक रिटायर्ड सूबेदार हैं।
- उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। फिर, उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की।
- **1990:** अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् में शामिल हुए।
- **2001- 2002:** तत्कालीन मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के विशेष कार्य अधिकारी।
- **2002-2008:** भाजपा के उत्तराखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
- **2012:** खटीमा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित; 2017 में फिर से चुने गए।
- **2016:** प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नियुक्त।
- **4 जुलाई, 2021** को पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

संगठनात्मक गतिविधियां भाजपा संसदीय दल बैठक

परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 मार्च, 2022 को नई दिल्ली के अम्बेडकर भवन में भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों को संबोधित करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी में परिवारवाद की राजनीति की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में संपन्न चुनावों में पार्टी द्वारा यदि किसी की उम्मीदवारी को खारिज किया गया है तो उसकी जिम्मेदारी वह स्वयं लेते हैं।

इससे पहले, चार राज्यों में भाजपा की जीत के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, श्री प्रल्हाद जोशी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस बैठक में शामिल हुए।

> चार राज्यों में भाजपा की जीत के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया

इस बैठक से पहले सभी नेताओं ने स्वरकोकिला लता मंगेशकर, यूक्रेन युद्ध के दौरान मृत हुए भारतीय छात्रों और कर्नाटक में मारे गए रा.स्व. संघ कार्यकर्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा।

पांच राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में से चार राज्यों में भाजपा सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही, इस भारी जीत के बाद यह पहली बैठक थी। ये चार राज्य हैं— उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की भारी जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सांसदों से परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया क्योंकि यह खतरनाक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेरी पहल का नतीजा है कि सांसदों के बच्चों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला क्योंकि हम परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा।

प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी को लेकर भी जानकारी साझा की।

विधानसभा चुनाव का जनादेश 'परिवारवाद' के खिलाफ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम 'परिवारवाद' के खिलाफ जनादेश है।

यह बैठक 14 मार्च से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के शुरू होने के बाद आयोजित की गई थी। बजट सत्र 08 अप्रैल, 2022 को समाप्त होगा। ■

बीरभूम हिंसा : भाजपा ने की सीबीआई जांच की मांग

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया और सांसद एवं पश्चिम बंगाल प्रदेश महामंत्री श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने 22 मार्च, 2022 को केंद्रीय कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में घटित घटना पर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और घटना की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कल रात एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद जो हुआ, वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वो बेहद दुःखद और चिंताजनक हैं। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बंगाल में सबसे ज्यादा अपराध वो लोग करते हैं, जिन्हें वहां की सत्तारूढ़ ममता बनर्जी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इन असामाजिक तत्वों ने कल रात 10-12 घरों के बाहर दरवाजे पर ताला लगा दिया, ताकि उन घरों में जब आग लगाई जाए, तो उन घरों में रहने वाले निर्दोष लोग भाग न पाएं। अब तक की ख़बरों के अनुसार इस घटना में 10 लोगों की मौतें हुई हैं जिसमें महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। एक ही घर से 7 शव निकाले गए हैं। वहां अराजकता ऐसी कि जब फायर ब्रिगेड की टीम आग पर नियंत्रण पाने के लिए घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें कुछ स्थानीय लोगों ने आग बुझाने से भी रोका।

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछना चाहती है कि प्रदेश में जिस प्रकार लोगों के घर जलाये जा रहे हैं, निर्दोष लोगों की नृशंस हत्याएं हो रही हैं, ऐसी स्थिति में ममता जी बताएं कि राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है? क्या पश्चिम बंगाल में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? पश्चिम बंगाल में लोगों पर बम ऐसे फेंके जाते हैं कि बम कोई खिलौना हो। सबसे दुःखद बात है कि जो असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन्हें सजा मिलनी तो दूर की बात, आम जनता को यह सन्देश दिया जाता है कि ये लोग टीएमसी के ही हैं, इनसे डर के रहना, अगर विरोध करने की हिम्मत की तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे, नृशंस हत्या की जायेगी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि इंसाफ की तराजू पर टीएमसी के गुंडे भारी पड़ रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी है जो इंगित करता हो कि वहां की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ममता जी, जब प्रथम द्रष्टया, प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाये रखने में आप सक्षम नहीं हैं और वहां के अपराधी तत्वों को आपका संरक्षण प्राप्त है तो यह सवाल स्वाभाविक है कि एक निष्पक्ष जांच कैसे होगी? भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फ़ौरन अपने पद से इस्तीफा दें। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने भी मांग की है और इस राष्ट्रीय मंच से भी हम यह मांग करते हैं कि बीरभूम घटना की सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच हो, ताकि घटना की सत्यता सामने आ सके। सबसे शर्मनाक बात यह है कि 10 लोगों की जानें जाने के बाद जब जांच की शुरुआत भी नहीं हुई थी, टीएमसी के जिला अध्यक्ष का यह कहना कि एक टीवी शॉट सर्किट के कारण तीन-चार घरों में आग लगी जिससे 10 लोगो की मौत हो गयी, निंदनीय भी है और चिंताजनक भी।

मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा पर अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोषियों को सजा दिलाने के लिए जो भी मदद की जरूरत है, मैं केंद्र से लेकर राज्य तक हर संभव मदद देने का आश्वासन देता हूं। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे अपराधियों को प्रोत्साहित करने वालों को भी माफ नहीं किया जाएगा।

– नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में हुई हिंसा में 10 निर्दोष लोगों की मौत से स्तब्ध हूं। ये घटना साबित करती है कि ममता सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। मैं इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं।

– जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

भाजपा ने पांच सदस्यीय समिति का किया गठन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बीरभूम हिंसा की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो घटना स्थल पर जाकर तथ्यों की जानकारी एकत्रित कर पार्टी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं राज्यसभा सांसद श्री बृजलाल, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर एवं बागपत से लोकसभा सांसद श्री सत्यपाल सिंह, पूर्व आईपीएस एवं राज्यसभा सांसद के श्री के. सी. राममूर्ति, पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद श्री सुकांतो मजूमदार और पूर्व आईपीएस एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुश्री भारती घोष शामिल हैं। ■

वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 48.4 प्रतिशत बढ़कर 13,63,038 करोड़ रुपये हुआ

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए (चौथी किस्त तक) अग्रिम कर संग्रह 16 मार्च, 2022 तक 6,62,896.3 करोड़ रुपये है, जो लगभग 40.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में 16 मार्च, 2022 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह 13,63,038.3 करोड़ रुपये रहा, जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की इसी अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 9,18,430.5 करोड़ रुपये था, इस प्रकार प्रत्यक्ष कर संग्रह में 48.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध संग्रह (16 मार्च, 2022 तक) में वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 42.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जब शुद्ध संग्रह 9,56,550.3 करोड़ रुपये था और वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में 34.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जब शुद्ध संग्रह 10,09,982.9 करोड़ रुपये था।

कुल 13,63,038.3 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में शामिल है— निगम कर (सीआईटी) 7,19,035.0 करोड़ रुपये (रिफंड शुद्ध) और सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) 6,40,588.3 करोड़ रुपये (रिफंड शुद्ध)। 16 मार्च, 2022 तक 13,63,038.3 करोड़ रुपये का संग्रह, जबकि लक्ष्य 11.08 लाख करोड़ रुपये (बीई) था और इसे संशोधित करते हुए 12.50 लाख करोड़ रुपये (आरई) निर्धारित किया गया था।

वित्त वर्ष 2021-22 (16 मार्च, 2022 तक) के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (रिफंड के समायोजन से पहले) पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 11,20,638.6 करोड़ रुपये की तुलना में 15,50,364.2 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सकल संग्रह 11,34,706.3 करोड़ रुपये रहा था, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में यह 11,68,048.7 करोड़ रुपये था।

कुल 15,50,364.2 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में निगम कर (सीआईटी) 8,36,838.2 करोड़ रुपये और सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) 7,10,056.8 करोड़ रुपये शामिल हैं। लघु शीर्षवार संग्रह (16 मार्च, 2022 तक) में शामिल हैं— अग्रिम कर 6,62,896.3 करोड़ रुपये; स्रोत पर कर कटौती 6,86,798.7 करोड़ रुपये; स्व-मूल्यांकन कर 1,34,391.1 करोड़ रुपये; नियमित मूल्यांकन कर 55,249.5 करोड़ रुपये; लाभांश वितरण कर 7,486.6 करोड़ रुपये और अन्य लघु शीर्षों के तहत कर 3,542.1 करोड़ रुपये।

वित्त वर्ष 2021-22 में 16 मार्च, 22 तक संचयी अग्रिम कर संग्रह 6,62,896.3 करोड़ रुपये है, जबकि पूर्ववर्ती वित्त वर्ष यानी 2020-21 की इसी अवधि के लिए अग्रिम कर संग्रह 4,70,984.4 करोड़ रुपये था, जो 40.75 प्रतिशत (लगभग) की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा 16 मार्च, 2022 (वित्त वर्ष 2021-22) तक संचयी अग्रिम कर संग्रह 6,62,896.3 करोड़ रुपये था और इसमें वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 50.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जब अग्रिम कर संग्रह (संचयी) 4,40,281.4 करोड़ रुपये था और इसमें वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में 30.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी, जब अग्रिम कर संग्रह (संचयी) 5,06,714.2 करोड़ रुपये था।

16 मार्च, 2022 तक 6,62,896.3 करोड़ रुपये के अग्रिम कर के आंकड़े में निगम कर (सीआईटी) 4,84,451.8 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) 1,78,441.1 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस धनराशि के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बैंकों से और जानकारी की प्रतीक्षा है। वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक 1,87,325.9 करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किए गए हैं। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 22 मार्च को 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी। यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडीएन3 के समतुल्य से टीडी5 ग्रेड) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4750/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 60.53 प्रतिशत का फायदा सुनिश्चित करेगा। 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।

यह लाभ के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है। यह जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक का लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है। ■

भारत ने 400 अरब डॉलर का उत्पाद निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल किया

भारत ने निर्धारित समय से नौ दिन पहले ही 400 अरब डॉलर का उत्पाद निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया। यह पहला मौका है जब भारत ने 400 अरब डॉलर मूल्य के वस्तुओं का निर्यात किया है। चालू वित्त वर्ष में भारत का निर्यात 37 प्रतिशत बढ़कर 400 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। वित्त वर्ष 2020-21 में यह 292 अरब डॉलर रहा था। निर्यात के मामले में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018-19 में 330 अरब डॉलर का रहा था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 400 अरब डॉलर का उत्पाद निर्यात लक्ष्य हासिल करने पर कहा कि देश को 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने में यह एक अहम पड़ाव है। साथ ही, श्री मोदी ने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं तथा निर्यातकों की सराहना की।

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को कहा कि भारत ने 400 अरब डॉलर मूल्य के वस्तुओं के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और देश ने पहली बार इस लक्ष्य को हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए अपने किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं तथा निर्यातकों को बधाई देता हूं। यह हमारी 'आत्मनिर्भर भारत' यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

भारत से वस्तु निर्यात चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से नौ दिन पहले ही 400 अरब डॉलर से अधिक हो गया। यह वित्त वर्ष 2018-19 में अर्जित 330 अरब डॉलर के पिछले रिकॉर्ड से बहुत अधिक है

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 400 अरब डॉलर का निर्यात हासिल करना देश के प्रत्येक सेक्टर, प्रत्येक हितधारक के ठोस, सामूहिक प्रयास का परिणाम है। भारत से वस्तु निर्यात चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि से नौ दिन पहले ही 400 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। यह वित्त वर्ष 2018-19 में अर्जित 330 अरब डॉलर के पिछले रिकॉर्ड से बहुत अधिक है।

श्री गोयल ने 23 मार्च को कहा कि इस आकर्षक निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति ने विश्व को दिखा दिया कि अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद दृढ़ संकल्प, लगन, क्षमता और प्रतिभा के साथ भारत सभी प्रकार की बाधाओं को पार करेगा। उन्होंने सभी निर्यातकों, किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, विनिर्माताओं, विदेश स्थित भारतीय मिशनों तथा अन्य हितधारकों के प्रति कृतज्ञता जताई।

श्री गोयल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आगे बढ़कर लगातार अगुवाई करने तथा निर्यात पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते रहने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई स्पष्ट अपील ने ही उद्योग को निर्यात में भारी उछाल लाने के लिए प्रेरित किया।

गौरतलब है कि कोविड की भीषण चुनौतियों के बावजूद भारत के वस्तु व्यापार प्रदर्शन ने प्रभावशाली बढ़ोतरी प्रदर्शित की तथा निर्यात अप्रैल से फरवरी के दौरान 11 लगातार महीनों (मार्च के अंत में लगातार 12 महीनों तक संभव) तक 30 अरब डॉलर से अधिक रहा, जिसमें विशेष रूप से दिसंबर, 2021 के दौरान 39.3 अरब डॉलर का अब तक का सर्वोच्च मासिक वस्तु व्यापार रिकॉर्ड किया गया।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 2021-22 के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा है। उच्चतर इंजीनियरिंग निर्यात, अपैरल तथा गारमेंट निर्यात आदि से संकेत मिलता है कि भारत की प्राथमिक वस्तुओं का प्रमुख निर्यातक होने की गलत धारणा अब धीरे-धीरे बदल रही है। अब हम अधिक से अधिक मूल्यवर्धित वस्तुओं तथा हाईएंड वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं।

सूती धागे/फैब्रिक्स/मेडअप्स/हथकरघा उत्पाद आदि, रत्न एवं आभूषण, अन्य अनाज तथा मानव निर्मित यार्न/फैब्रिक्स/मेडअप्स आदि के निर्यात ने 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच की वृद्धि दर दर्ज कराई है।

कृषि क्षेत्र ने भी, विशेष रूप से महामारी के दौरान उल्लेखनीय प्रगति दर्ज कराई, जिसमें भारत खाद्य/अनिवार्य कृषि उत्पादों के एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरा है। कृषि निर्यात में उछाल अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त चावल (बासमती तथा गैर-बासमती दोनों), समुद्री उत्पादों, गेहूं, मसालों तथा चीनी जैसी वस्तुओं से प्रेरित है, जिसने 2021-22 के दौरान अब तक का सर्वाधिक कृषि उत्पाद निर्यात दर्ज कराया। ■

देश में 12-14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू

12 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को बायोलॉजिकल-ई के कोर्बेवैक्स टीके की दो खुराकें 28 दिनों के अंतराल में दी जाएगी

देश में 12 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान 16 मार्च को शुरू हो गया और इन किशोरों को कोर्बेवैक्स टीके की खुराक दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती खुराक देने के लिए अन्य बीमारियों से पीड़ित होने की शर्त हटाने का भी फैसला किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 'सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन' अभियान के तहत 12-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू हो चुका है। 60 साल से अधिक आयु के सभी लोग आज से एहतियाती खुराक ले सकेंगे। आइए, मिलकर देश सुरक्षित करें, टीका लगवाएं।

दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 12 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को बायोलॉजिकल-ई के कोर्बेवैक्स टीके की दो खुराकें 28 दिनों के अंतराल में दी जाएगी।

इसके साथ ही 60 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को

अब एहतियाती खुराक दी जा सकती है और कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक देने की तारीख से नौ महीने पूरे होने के आधार पर यह एहतियाती खुराक दी जाएगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार एहतियाती खुराक उसी टीके की दी जाएगी जो प्रमुख टीकाकरण अभियान के दौरान उस व्यक्ति को दी गयी थी। ■

देशवासियों के टीकाकरण के भारत के प्रयासों में आज का दिन महत्वपूर्णः नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 मार्च को कहा कि देशवासियों के टीकाकरण के भारत के प्रयासों में आज का दिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने 12-14 आयुवर्ग के किशोरों तथा 60 वर्ष से अधिक सभी लोगों को टीका लगवाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने शृंखलाबद्ध ट्वीट में कहा कि हमारे देशवासियों के टीकाकरण के भारत के प्रयासों में आज का दिन महत्वपूर्ण है। अब से 12-14 आयुवर्ग के किशोर टीका लगवाने के तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग प्रीकॉशन डोज लगवाने के पात्र हो गये हैं। मैं टीका लगवाने के लिये इस आयुवर्ग के सभी लोगों का आह्वान करता हूं।

श्री मोदी ने कहा कि पूरे विश्व की देखभाल करने की भारत की भावना के अनुरूप हमने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत कई देशों को टीके भेजे। मुझे खुशी है कि टीकाकरण के भारत के प्रयासों ने कोविड-19 के विरुद्ध विश्व की लड़ाई को मजबूत किया है।

उन्होंने कहा कि आज, भारत के पास कई 'मेड इन इंडिया' वैक्सीनें हैं। हमने मूल्यांकन की आवश्यक प्रक्रिया के बाद अन्य वैक्सीनों को भी अनुमति प्रदान की है। हम इस जानलेवा महामारी से लड़ने में काफी बेहतर स्थिति में हैं। साथ ही, हमें कोविड सम्बंधी सावधानियों का भी पालन करना होगा।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 12-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण की शुरुआत पर कहा कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर देश की भावी पीढ़ी को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए आज से देशभर के 12-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। साथ ही, 60 वर्ष के ऊपर के सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। कोरोना मुक्त भारत के लिए 'टीका जीत का' अवश्य लगवाएं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि हर भारतीय के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिबद्ध श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी के लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत आज से 12-14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए एहतियाती खुराक की शुरुआत हो गयी है। इस आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका लगवाना चाहिए। ■

लोग, जो हमें प्रेरणा देते हैं

पं. दीनदयाल उपाध्याय

भारतीय जनसंघ अलग तरह का दल है। यह उन लोगों का समूह नहीं है, जो किसी भी तरह सत्ता पाना चाहते हैं। न ही यह किसी निहित स्वार्थ विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि केवल अपने पक्ष में प्रचार करने तक सीमित हो। इन्हें इस बात का भी कोई दुःख नहीं है कि जब ब्रिटिश भारतीयों को सौंपकर गए तो यहां के शासकों ने इन्हें सत्ता में हिस्सेदार नहीं बनाया। वास्तव में जनसंघ की नींव रखनेवाले प्रथम अध्यक्ष श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्री परिषद् के सदस्य थे और पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों की रक्षा के मुद्दे पर उनके त्याग-पत्र के पश्चात् ही इस नए दल की स्थापना का विचार आया।

जनसंघ उन लोगों का जमावड़ा भी नहीं है, जो कि इस नए युग के आगमन से राजनीतिक और आर्थिक रूप से विस्थापित हुए हैं। इसके किसी सदस्य के नाम के साथ 'पूर्व' उपसर्ग शायद ही लगाया जा सकेगा। अपने अतीत की कमाई पर जाने की अपेक्षा हम अपने वर्तमान के कर्मों पर निर्भर हैं। यद्यपि जनसंघ की व्याख्या प्रसिद्ध 'नेति नेति' शब्दों में की जा सकती है, जिससे विपक्षी संतुष्ट न होंगे। यद्यपि यह बात ही सत्य है। इसलिए वे पूछ सकते हैं कि "आखिरकार यह है क्या?"

जनसंघ दल नहीं, आंदोलन है

सचमुच भारतीय जनसंघ एक दल न होकर एक आंदोलन है। यह भारत के आत्मस्वरूप की प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा से पैदा हुआ है। राष्ट्र को जो नियति तय है, उसे आकार देने और प्राप्त करने की यह इच्छा है। यह केवल मात्र लोगों की उस इच्छा की अभिव्यक्ति है, जो खुली हवा में सांस लेना चाहती है, उन शारीरिक और मानसिक बंधनों से मुक्ति चाहती है, जिन्होंने हमारी आत्मा को बंदी बनाकर इस राष्ट्र को गरुड़ की तरह सर्वोच्च शिखर तक उड़ने से रोक रखा है, जहां पहुंचकर यह उस सर्वोच्च का अंग बन सके। यह सृष्टि क्रम में अपना स्थान खोजने का प्रयास है, ताकि राष्ट्र के रूप में सोद्देश्य और सुखी जीवन जी सकें और मानवता की सेवा कर सकें।

भारतीय संस्कृति और मर्यादा जनसंघ के आधार हैं। भारतीय संस्कृति कुछ विशिष्ट लोगों की संस्कृति की परिचायक न होकर एक विश्व-दर्शन की परिचायक है। यह बंटे हुए विश्व को एक कर शांति प्रदान कर सकती है। सह-अस्तित्व और एकता के आदर्श मात्र राजनीतिक नारेबाजी बनकर रह जाएंगे, यदि इस महान् संस्कृति से अनुप्राणित नहीं होंगे। यह हमारा जीवन लक्ष्य है। दायित्व वहन और कर्तव्य निर्वहन भी उत्कट इच्छा को पश्चिम की यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने शासन के औचित्य को ठहराने के लिए गढ़े गए 'सफेद लोगों का बोझा' सिद्धांत के तुल्य नहीं मानना चाहिए। भूरे लोगों का कोई बोझा नहीं है। हमें न ऐसे भ्रम हैं और न हमारी ऐसी योजनाएं हैं। हमारी भूमिका उपदेशकों की नहीं, उदाहरण पेश करनेवालों की है। सदा से यही हमारा मार्ग रहा है। मनुस्मृति में कहा गया है, "माशा भर व्यवहार मनों उपदेशों से बेहतर है।" यह एक पुरानी कहावत है। हमारे लिए इसमें एक शिक्षा है।

भारतीय संस्कृति क्या है ?

इस छोटे से लेख में मेरा उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन अथवा उसकी व्याख्या करना नहीं है। यह विखंडनात्मक या विश्लेषणात्मक न होकर समग्रतावादी है। यह जैविक है, मिश्रित नहीं। यह समग्र मनुष्य को न केवल समाज का बल्कि सृष्टि का अंग मानती है। पश्चिम के अनेक दर्शनों में मनुष्य को सृष्टि में सर्वोपरि स्थान देने के बावजूद वहीं पर अमानवीयकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। मनुष्य को पुनर्जीवित और उदात्त बनाने के लिए, जीवन दर्शन को मानवीय बनाने, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं को अधिक मानवीय बनाने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति यही कार्य करने का प्रयास करती है। यह कहना कि इसमें चरम शिखर पर पहुंच गए बड़बोलेपन, शोध की आत्मा के विपरीत और विकास के विरुद्ध कथन होगा, परंतु इस दिशा में गंभीर प्रयास हुआ है और जो सफलता मिली है, उससे आशा जगती है कि और सफलता के लिए प्रयास करें।

भारतीय संस्कृति जड़ न होकर गतिशील है। वास्तव में गतिशीलता ही जीवन है। जब आपका विकास रुक जाता है, आप निष्क्रिय होने लगते हैं और निष्क्रियता बिखराव तथा मृत्यु की ओर ले जाती है। अपने स्वर्णिम अतीत और दुर्दशापूर्ण वर्तमान के कारण समाज में दो तरह की प्रवृत्तियां प्रचलित हैं। एक पुरातन को स्वीकारती है जो कि वास्तव में इसे अपना संस्कार मानती है, जिस पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता। दूसरी प्रवृत्ति परिवर्तन की लालसा हर क्षेत्र में रखती है और इस बात की भी चिंता नहीं करती कि परिवर्तन की दिशा क्या हो और उसकी शक्ल क्या बनती है। जनसंघ इन दोनों प्रवृत्तियों का निषेध करती है। अतीत से हम प्रेरित हों। परंतु हमारी दृष्टि अग्रगामी होनी चाहिए। जो कुछ हमें विरासत में मिला है, उस सारे को सुरक्षित रखना पूर्वजों की सेवा नहीं है। हमें तो गुलामी भी विरासत में मिली थी। मनुष्य ने अपनी इस विरासत से मुक्ति के लिए कठोर संघर्ष किया है। इस तरह हज़ारों अन्य विरासतें हो सकती हैं। इनसे मुक्ति ही एकमात्र उपाय है। उधार चुकाया जाना चाहिए और पूंजी की सुरक्षा तथा परिवर्धन होना चाहिए। जो लोग केवल संरक्षण की बात करते हैं, वे प्रकृति के नियमों को भूल जाते हैं। ■

- ऑर्गनाइज़र, दीवाली, 1964 (अंग्रेज़ी से अनूदित)

कुशल संगठक सुन्दर सिंह भण्डारी

(12 अप्रैल, 1921 — 22 जून, 2005)

शत-शत नमन

कुशल संगठक श्री सुन्दर सिंह भण्डारी का जन्म 12 अप्रैल, 1921 को राजस्थान स्थित उदयपुर के एक जैन परिवार में हुआ था। मूलतः उनका परिवार भीलवाड़ा के मण्डलगढ़ से संबंध रखता था, परन्तु उनके दादा वहां से उदयपुर चले गए। श्री भण्डारी के पिता डॉ. सुजान सिंह भण्डारी एक डॉक्टर थे। इस कारण उन्हें सदैव घूमते रहना पड़ता था। श्री भण्डारी की शिक्षा कई स्थानों पर हुई। उन्होंने उदयपुर से सिरोही से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की और डीएवी कॉलेज, कानपुर से बी.ए. और एम.ए. किया। उन्होंने अर्थशास्त्र में एम.ए. पास किया और बाद में कानून का अध्ययन किया।

शांत भाव के श्री भण्डारी जीवन भर अविवाहित रहे और राष्ट्र की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। 1942 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद श्री भण्डारी ने मेवाड़ उच्च न्यायालय में लीगल प्रेक्टिस शुरू की। 1937 में उन्होंने एस.डी. कॉलेज, कानपुर में प्रवेश लिया, जहां पं. दीनदयाल उपाध्याय उनके सहपाठी थे। 1937 में इंदौर के बालू महाशब्दे ने उन्हें कानपुर के निकट नवाबगंज की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ले गए थे। तब से वे सदैव अपनी अंतिम सांस तक रा. स्व. संघ की विचारधारा के प्रति समर्पित रहे।

1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। रा. स्व. संघ से जिन प्रमुख कार्यकर्ताओं को जनसंघ में कार्य के लिए भेजा गया था, उनमें श्री भण्डारी का नाम प्रमुख रूप से शामिल था। 1951 से 1965 तक श्री भण्डारी ने राजस्थान जनसंघ में महामंत्री का दायित्व निभाया। इसके अलावा वे जनसंघ के अखिल भारतीय मंत्री थे। पं. दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद 1968 में भण्डारी जी को अखिल भारतीय महामंत्री (संगठन) बनाया गया।

उन्होंने 1977 तक जनसंघ महामंत्री के पद पर कार्य किया। वह 1966–1972 के समय राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1998 में उन्हें बिहार का राज्यपाल और 1999 में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया। भण्डारी जी ने कार्यकर्ताओं के सामने सरलता, सहनशीलता और मितव्ययता का उदाहरण पेश किया।

उन्होंने अनुशासित पार्टी की छवि कायम रखी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उच्च जीवन-शैली बनाए रखने का आह्वान किया। वह एक ऐसे मूर्तिकार और कार्यकुशल कारीगर थे, जिन्होंने मानव, समाज और संगठन की प्रतिमा बनाई। वह कभी भी 'कलश' नहीं बनना चाहते थे। वे अत्यंत स्पष्टवादी थे। अपनी प्रकृति के कारण वे कार्यकर्ताओं में 'हेडमास्टर' के नाम से सुप्रसिद्ध हो गए। उन्होंने अपना सारा जीवन मातृभूमि को समर्पित किया तथा जीवनभर के रा.स्व. संघ के प्रचारक बने रहे। 22 जून, 2005 को उनका स्वर्गवास हो गया। ■

श्री सुन्दर सिंह भण्डारी ने अनुशासित पार्टी की छवि कायम रखी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उच्च जीवन-शैली बनाए रखने का आह्वान किया। वह एक ऐसे मूर्तिकार और कार्यकुशल कारीगर थे, जिन्होंने मानव, समाज और संगठन की प्रतिमा बनाई। वह कभी भी 'कलश' नहीं बनना चाहते थे। वे अत्यंत स्पष्टवादी थे। अपनी प्रकृति के कारण वे कार्यकर्ताओं में 'हेडमास्टर' के नाम से सुप्रसिद्ध हो गए

जनादेश, मतदाता संदेश व राजनीतिक निहितार्थ

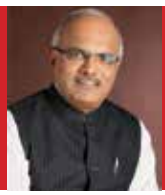

डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे
अध्यक्ष, आईसीसीआर
सदस्य, राज्य सभा

जनादेश में हमेशा एक संदेश होता है और यह इस पर निर्भर करता है कि प्राप्तकर्ता इसे कैसे पढ़ता हैं। हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान भी यह बात सही साबित हुई। भारत में चुनावी नतीजों ने हमेशा इस तथ्य को रेखांकित किया है कि निरंतरता और परिवर्तन हमेशा साथ-साथ चलते हैं और मौजूदा विभानसभा चुनाव भी इसमें कोई अपवाद नहीं है। मतदाताओं ने बदलाव की राजनीति पर जहां अपना भरोसा जताया, वहीं ठहराव की राजनीति के समर्थक लोगों की बदलाव की मांग को ठुकरा दिया।

मतदाताओं की आवाज

मतदाताओं के स्पष्ट और जोरदार संदेश के चार पहलू हैं। सबसे पहले, उत्तर प्रदेश के परिणामों ने विशेष रूप से दिखाया है कि मतदाताओं ने जाति और समुदाय से ऊपर उठकर, कल्याणकारी और विकासात्मक राजनीति के पक्ष में मतदान किया है। वी.पी. सिंह के युग से शुरु होकर राजनीति सामाजिक गठजोड़ या सोशल इंजीनियरिंग से प्रभावित रही, लेकिन अब लोकतांत्रिक राजनीति को एक अलग स्तर पर ले जाया गया है और आकांक्षाओं के प्रभावी प्रबंधन ने सोशल इंजीनियरिंग की जगह ले ली है। जनता जाति और समुदाय के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टियों की तुलना में जमीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी को पसंद कर रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य में बहुजन समाज पार्टी का पतन इस बात का द्योतक है कि अनुसूचित जातियों ने समुदाय विशेष पर आधारित पार्टी के साथ जुड़ने से इनकार कर दिया है।

परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं

दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि परिवारवादी राजनीति के दिन अब समाप्त हो गए हैं। मतदाताओं ने एक के बाद एक परिवारवादी दलों को खारिज किया है, बादल परिवार से लेकर यादवों और बनर्जी तक, इस सबसे भी बढ़कर गांधी परिवार तक।

- **मतदाताओं ने बदलाव की राजनीति पर जहां अपना भरोसा जताया, वहीं ठहराव की राजनीति के समर्थक लोगों की बदलाव की मांग को ठुकरा दिया**
- **मतदाताओं ने जाति और समुदाय से ऊपर उठकर, कल्याणकारी और विकासात्मक राजनीति के पक्ष में मतदान किया है**
- **परिवारवादी राजनीति के दिन अब समाप्त हो गए हैं। मतदाताओं ने एक के बाद एक परिवारवादी दलों को खारिज किया है, बादल परिवार से लेकर यादवों और बनर्जी तक, इस सबसे भी बढ़कर गांधी परिवार तक**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रचार अभियान के दौरान मतदाताओं को परिवारवादी पार्टियों के बारे में आगाह किया था और ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने उनकी अपील को स्वीकार किया है। एक आकांक्षी लोकतंत्र में जनता अब महसूस करने लगी है कि परिवारवादी दलों के नेताओं का समर्थन करना जन्म-आधारित भेदभाव का समर्थन करने जैसा है, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने भी खारिज कर दिया था। जिन पार्टियों में नेतृत्व केवल परिवारों का एकाधिकार है, उनका भविष्य गौरवशाली नहीं हो सकता और जितनी जल्दी परिवारवादी इस संदेश को स्वीकार करते हैं, उनके अस्तित्व के लिए यह उतना ही अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) जैसी पार्टियां इस संदेश पर गंभीरता से विचार करेंगी। हमें आम आदमी पार्टी (आप) को लेकर भी कोई संशय नहीं रखना चाहिए, हालांकि यह एक परिवारवादी पार्टी नहीं है, लेकिन इसे भी उसी तर्ज पर चलाया जा रहा है। बहरहाल, पंजाब में जीत भी एक पारंपरिक विकल्प को लेकर जनता की स्पष्ट अस्वीकृति है, जिसका नाता भी परिवारवादी पार्टी से रहा है।

प्रदर्शन पर जोर

तीसरा संदेश प्रदर्शन की राजनीति को लेकर है। जो पार्टियां इस बात को सुनिश्चित करने में सफल रही हैं कि उनकी सरकारें सत्ता में आने पर काम करती हैं, वह सत्ता विरोधी लहर को सत्ता समर्थक लहर में बदलने में कामयाब हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 2019, महाराष्ट्र में 2020, बिहार में 2020, असम में 2021 और अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में इस बात को साबित किया है। इन सभी दौर के चुनावों में भाजपा की जीत केवल एक कमजोर विपक्ष के कारण नहीं हुई है। दरअसल, यूपी, गोवा, उत्तराखंड या इससे पहले गुजरात या महाराष्ट्र में विपक्ष को बिल्कुल भी कमजोर नहीं कहा जा सकता। और फिर भी, अगर लोगों ने इन चुनावों में स्पष्ट रूप से भाजपा को समर्थन दिया है, तो यह सत्ता समर्थक होने का स्पष्ट संकेत है।

'नयी वैश्विक व्यवस्था में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 मार्च को उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 96वें सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया की नजर भारत पर टिकी है और कोविड महामारी के बाद जो नयी वैश्विक व्यवस्था उभर रही है, उसमें भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है और साथ ही तेज गति से अपना विकास भी सुनिश्चित करना है।

श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य 'आत्मनिर्भर भारत' का है और किसी भी सूरत में इस अवसर को खोना नहीं है।

उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के जिस मुकाम पर आज भारत है, पूरी दुनिया की नजरें हम पर टिकी हुई हैं। कोविड ने जो परिस्थितियां पैदा की हैं, उसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर (वैश्विक व्यवस्था) उभर रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी भूमिका बढ़ानी है और तेज गति से अपना विकास भी करना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षुओं को एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि 21वीं सदी के भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य 'आत्मनिर्भर भारत' और 'आधुनिक भारत' का है। उन्होंने कहा कि इस समय को हमें खोना नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि सेवा और कर्तव्य भाव का महत्व प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का अभिन्न हिस्सा रहा है और उन्हें इस भाव को अपनी सेवा के दौरान भी बनाए रखना होगा तभी वह समाज व देश के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बन सकेंगे।

उन्होंने कहा कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने में 25 साल बचे हैं और इसमें देश कितना विकास करेगा, उसमें इन प्रशिक्षुओं की बहुत बड़ी भूमिका होगी।

श्री मोदी ने कहा कि बीते 75 वर्षों में

हमने जिस गति से प्रगति की है, अब उससे कई गुना तेजी से आगे बढ़ने का समय है। इसलिए, आपको फाइलों और फील्ड के कामकाज के अंतर को समझना है। फाइलों में आपको असली चीज नहीं मिलेगी, फील्ड के लिए आपको उससे जुड़ा रहना ही पड़ेगा। फाइलों में जो आंकड़े होते हैं, वह सिर्फ नंबर नहीं होते हैं। हर एक आंकड़ा...हर एक नंबर एक जीवन होता है और हमें इसके महत्व को समझना होगा।

उन्होंने कहा कि जीवन में हर एक व्यक्ति के कुछ सपने होते हैं और उनकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं। आपको उनकी कठिनाइयों और चुनौतियों के लिए काम करना है। ■

मजे की बात यह है कि सत्ता विरोधी लहर एक तरह की यथास्थिति का नियम बन गई थी; अब, यह नियम स्पष्ट रूप से बदला हुआ है। यह बात भी स्पष्ट है कि अधिकांश राज्यों में भाजपा ने अपने मत-प्रतिशत में वृद्धि की है। इस बात को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस जीत को 'भाजपा के गरीब समर्थक, सक्रिय शासन' के रूप में वर्णित किया है।

नेतृत्व की महत्ता

अंत में, 2022 के नतीजे इस बात को रेखांकित करते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा मायने रखता है, चाहे कोई राज्य कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। अतीत में कई बार राजनीतिक पंडितों ने कहा है कि राष्ट्रीय चुनावों के नतीजे राज्य की राजनीति से प्रभावित होते हैं। आज, 2022 के नतीजे हमें याद दिलाते हैं कि राज्य के नतीजे भी राष्ट्रीय आकांक्षाओं से प्रभावित होते हैं। ये चुनाव कोविड-19 महामारी की छाया में हुए। इसके अलावा, जब मतदान का दौर वास्तव में शुरू हुआ, तो यूक्रेन संकट भी खबरों में स्थान पा रहा था, क्योंकि वहां हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए थे। चाहे वह कोरोना वायरस महामारी हो या यूक्रेन में फंसे भारतीय, सरकार ने इन चुनौतियों का जिस तरह से सामना किया, उसे देश भर की जनता ने सकारात्मक तौर पर लिया है। यह इस बात का भी द्योतक है कि पूरे भारत में लोग मानते हैं कि देश को कई और वर्षों तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की जरूरत है। इन राज्य के फैसले इस भावना को दर्शाते हैं।

ये चुनाव परिणाम लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। जैसाकि लोकतंत्र को लेकर 'संतुष्टि' पर प्यू रिसर्च सेंटर की नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, 'वैश्विक महामारी ने कथित राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ाया है। 2021 में हमने जिन 17 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया, उनमें 61 प्रतिशत का कहना है कि उनका देश महामारी के प्रकोप से पहले की तुलना में अधिक विभाजित हुआ है। वहीं, भारत के परिपेक्ष्य में देखा जाए तो कोविड-19 की तीन लहरों के बाद संपन्न हुए चुनावों में विभिन्न क्षेत्रों और दूर-दराज में रहने वाली जनता ने एक तरफा मतदान किया है। इस बात से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री राज्यों, जातियों और समुदायों के बीच एक उत्कृष्ट एकीकृतकर्ता के रूप में उभरे हैं। कार्यान्वयन की कला में महारत हासिल करने के बाद, उन्होंने स्थापित किया है कि उदार लोकतंत्र कुशल राज्य निर्माण के साथ चल सकता है। 2022 के नतीजों का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है क्योंकि वह भाजपा के मजबूत संगठन और विचारधारा को लेकर चलते हैं। ■

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास

लाल सिंह आर्य
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
अनु.जाति मोर्चा, भाजपा

प्राचीन से लेकर आधुनिक दुनिया के अनेक महापुरुषों ने अपने कर्मों, सुधारों, आंदोलनों और सेवाभाव से समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। आधुनिक दुनिया में ऐसे ही एक बहुचर्चित व्यक्तित्व हैं बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर, जिन्होंने हाशिये से उठकर एक बेहतर दुनिया बनाने में अपने बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने वंचितों के मानवाधिकारों पर जोर देने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ी और प्रत्येक व्यक्ति के न्याय और समान गरिमा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. अंबेडकर ने भारत को न्यायपूर्ण समाज बनाने और राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखा था। उन्हें, दुर्भाग्य से, विभिन्न कारणों से, केवल 'दलितों के मसीहा' के रूप में चित्रित किया गया। केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सफल सरकारें, उनके वास्तविक योगदान के बारे में लोगों को शिक्षित करने में अनजाने में या जानबूझकर विफल रही हैं। आज यह स्वीकार करने की जरूरत है कि वह अर्थशास्त्र में गहरी जानकारी रखने वाले आधुनिक भारत के पहले राजनीतिक नेता थे। उन्होंने दो विदेशी विश्वविद्यालयों से पीएचडी की डिग्री ली थी, 12 भाषाएं जानते थे, एक न्यायविद, विपुल लेखक, प्रशासक आदि थे जो उन्हें अपने समय में सबसे योग्य भारतीय बनाते थे।

डॉ. अंबेडकर द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के असंतोष ने उन्हें कभी भी भारत के इतिहास में अपनी वास्तविक जगह नहीं मिलने दी। हालांकि, डॉ. अंबेडकर को पहला कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन नेहरू कभी भी उन्हें समकालीन राजनीति का अहम खिलाड़ी नहीं मानते थे। आजादी से पहले भी अपनी किताब 'द डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में नेहरू ने एक बार भी डॉ. अंबेडकर का जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा गांधी जी और डॉ. अंबेडकर के बीच मतभेद अब काफी खुले हैं लेकिन नेहरू और डॉ. अंबेडकर के बीच संवाद और असहमति

के बारे में शायद ही हमें पढ़ने को मिले। बाबा साहेब जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जे के लिए नेहरू की वकालत स्वीकार करने से हिचक रहे थे। उन्होंने प्रावधान 370 का विरोध किया और कहा कि धारा 370 को शामिल करके वह किसी भी कीमत पर भारत की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। जहां सरदार पटेल और डॉ. अंबेडकर जैसे लोगों ने देश के सामाजिक एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ीं, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश के आर्थिक और सामाजिक दोनों एकीकरण के लिए प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों में, 'बाबासाहेब ने समता (समानता) और ममता (मातृप्रेम) के संयोजन का प्रतिनिधित्व किया, जिसने समरसता (सामाजिक सद्भाव) लाया। डॉ. अंबेडकर की सोच और विरासत की झलक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की जनहितैषी, गरीब हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों से मिलती है। केंद्र सरकार अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के माध्यम से नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पंचतीर्थ का विकास — जन भूमि (महू), शिक्षा भूमि (लंदन), चैत्य भूमि (मुंबई), दीक्षा भूमि (नागपुर), महापरिनिर्वाण भूमि (दिल्ली) - राष्ट्रवादी सुधारक डॉ. अंबेडकर के लिए एक उचित विरासत सुनिश्चित करने की दिशा में कदम हैं। अगस्त, 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर, डॉ. अंबेडकर के विज़न को पूरा करते हुए ऐतिहासिक गलत को सही करने का साहसिक निर्णय लिया। अब जम्मू-कश्मीर के लोग विजन-ओरिएंटेड डेवलपमेंट की नई सुबह का अनुभव कर रहे हैं। इसने जम्मू-कश्मीर में नौ संवैधानिक संशोधनों और 106 अन्य कानूनों के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया है।

डॉ. अंबेडकर से प्रेरित होकर वर्तमान सरकार ने श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना फरवरी, 2019 में शुरू की गई थी ताकि असंगठित श्रमिकों को उनके बुढ़ापे में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। श्रम सुविधा पोर्टल जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से श्रम कानून को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। सरकार ने मौजूदा केंद्रीय श्रम कानूनों के प्रावधानों को चार श्रम संहिताओं में व्यवस्थित और तर्कसंगत बनाएं - मजदूरी पर श्रम संहिता, औद्योगिक संबंधों पर, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर और व्यावसायिक सुरक्षा पर, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत, गरीबों में से सबसे गरीब या अंत्योदय के उत्थान के दर्शन को एक नई जमीन मिली है और इसका उद्देश्य हमारी मानव पूंजी को सबसे बड़ी संपत्ति बनाना है। वर्तमान सरकार द्वारा समाज के कमजोर और गरीब वर्ग के उत्थान के लिए एक सुस्पष्ट और लक्षित दृष्टिकोण की अवधारणा की गई है।

28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबों के लिए सुलभ और लचीली वित्तीय सेवाओं के प्रावधान के इर्द-गिर्द घूमती है। यह पहल एक गेम-चेंजर रही है, जो कई गरीबी उन्मूलन पहलों की नींव के रूप में कार्य करती है, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ होता है। आज तक 44.88 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें लाभार्थी के खातों में लगभग 162,718.42 करोड़ रुपये शेष हैं।

हमारी माताओं-बहनों को खाना बनाते समय जो खतरनाक धुएं का सामना करना पड़ता है, उससे बचाने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। अब तक इस योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम-किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार पूरे भारत में 14.5 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपये की तीन किस्तों में हर साल 6,000 रुपये की पेशकश करती है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक, केंद्र सरकार ने देश के 9.5 लाख से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक सीधे हस्तांतरित किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए आवास सुविधा स्थापित करने के लिए दूरदर्शी भाजपा सरकार की पहल है। 20 मार्च, 2022 तक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1.15 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 94.79 लाख घरों को जमीनी स्तर पर तैयार किया गया है और लगभग 56.2 लाख घरों को पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को न केवल ऋण प्रदान करके बल्कि उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के लिए सशक्त बनाना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में अपने कारोबार को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए एक वर्ष के कार्यकाल के 10,000 रुपये तक के मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है, जिसमें आसपास के पेरी-शहरी/ ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना के तहत कुल 2 मिलियन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 752191 स्वीकृत किए गए हैं और 218751 ऋण पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

'आयुष्मान भारत' दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, जिसके 50 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत अब तक 1,36,4880 निःशुल्क उपचार किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 'एक राष्ट्र एक योजना' के अनुरूप कृषि बीमा के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसलों की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना है, कीट-पतंग और बीमारियां। इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। अनुसूचित जातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ASIIM (अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन) की स्थापना की गई थी। इस मिशन के तहत 1000 अनुसूचित जाति के युवाओं को उनके स्टार्ट-अप विचारों को वाणिज्यिक उद्यमों में बदलने के लिए 30 लाख रुपये और तीन साल की अवधि आवंटित की गई थी। इसी तरह अनुसूचित जाति के उद्यमियों को रियायती वित्त मुहैया कराने के उद्देश्य से एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की गई। इसने पहले ही 89 कंपनियों को 278.77 करोड़ रुपये का वितरण कर दिया है। उनकी शिक्षा में सहायता के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति लाई गई है, जिसके लिए 2025-26 तक 59,000 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं। संविधान के दो मंत्र — 'भारतीयों की गरिमा' और 'भारत की एकता' के अनुरूप सरकार के हालिया प्रयास हैं। जबकि कांग्रेस ने लगभग छह दशक तक देश में शासन किया, लेकिन बुनियादी सेवाओं (जैसे बिजली, पानी, बैंक खाते, शौचालय, घर आदि) का विकास उन चीजों से दूर था, जो आवश्यक थीं और जो वास्तव में प्राप्त करने योग्य थीं। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण योजना के तहत 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज को बढ़ाकर 98 प्रतिशत कर दिया है, जो 2 अक्टूबर, 2014 को मुश्किल से 38.7 प्रतिशत था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने यह भी दिखाया है कि हाल के वर्षों में मील के पत्थर के बाद क्या संभव है और क्या हासिल किया जा सकता है। उन्होंने 2020-21 में 12,205.25 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया, जिसमें प्रति दिन 34 किलोमीटर का निर्माण किया गया। यह 2014-15 में लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन के राजमार्गों के निर्माण की दर से लगभग तीन गुना था। पिछले कुछ वर्षों में यह सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भोजन, किफायती आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा जैसी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करके गरीबों को सशक्त बना रही है। डीबीटी प्रणाली के तहत इस सरकार ने 8.22 लाख करोड़ रुपये (2014 के बाद से) वितरित किए हैं, जो केंद्र सरकार के कल्याण और सब्सिडी बजट का लगभग 60 प्रतिशत है, सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान यह बेहद मददगार रहा और लाखों लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया गया। ■

कश्मीर फाइल्स: ऐतिहासिक मोड़

बैजयंत जय पांडा
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा

कश्मीर फाइल्स' फिल्म को देश भर में अभूतपूर्व सफलता मिल रही है और हर गुजरते दिन के साथ यह नए रिकॉर्ड बना रही है। हालांकि, 'कश्मीर फाइल्स' जैसी फिल्म की सफलता को केवल बॉक्स ऑफिस नंबरों के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। किसी भी बड़े अभिनेता की अनुपस्थिति और बॉलीवुड द्वारा कम समर्थन के बावजूद जनता द्वारा फिल्म को अभूतपूर्व रूप से स्वीकार करना इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक विषय अभी भी भारत के फिल्म उद्योग में मूल्यवान है। यह फिल्म कई अन्य मामलों में भी अलग रही है। उदाहरण के लिए, कश्मीर पर पूर्व में बनी फिल्मों के विपरीत, यह एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसने कश्मीरी पंडितों की जन-संहार और 'जातीय सफाई' की दुर्दशा की कड़वी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत की है, न कि प्रेम कथाओं के रूप में इसे छुपाया गया है। दूसरा, यह फिल्म भारतीय जनता की चेतना में एक विशेष प्रकार के कुप्रचार को बिठाने की गहरी साजिश के एक हिस्से के रूप में अक्सर बॉलीवुड फिल्मों के माध्यम से घुमाए गए कहानी से अलग है, जो स्वागत योग्य है। कश्मीरी पंडितों के जन-संहार, मारीचझापी हत्याकांड आदि जैसी घटनाओं को जनता से छिपाने के लिए मीडिया, बॉलीवुड के द्वारा लंबे समय से एक ठोस प्रयास किया गया है और पिछली सरकारें इस अन्याय के पक्षकार रही हैं। कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों की संघर्ष भरी कहानी बताने की कोशिश की है, जो घाटी में उग्रवाद और आतंकवाद से तबाह हो गए हैं, इस फिल्म में कठोर तथ्यों के आधार पर और दु:खद पलायन को जन-संहार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे जानबूझकर निहित स्वार्थों के कारण मीडिया और पिछली सरकारों के द्वारा शेष भारत से दूर रखा गया था। यह हिंसा के अंतहीन चक्र, अलगाववाद की कहरों, पाकिस्तान द्वारा वित्त पोषित आतंकी संगठनों की घुसपैठ और लोगों के बीच बढ़ते असंतोष और पत्रकारिता के कुप्रचार के बारे में बात करता है। इसमें 5 लाख कश्मीरी पंडितों के न्याय के लिए संघर्ष, यातना और कई वर्षों के इंतजार की पीड़ा को दर्शाया गया है।

फिल्म को मिला अपार प्यार और समर्थन भारत में हो रहे बदलाव के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। भारतीय समाज और विशेष रूप से युवा वास्तव में एक परिवर्तनकारी बदलाव के कगार पर हैं, जहां एक फिल्म जो राष्ट्रवाद की भावना के साथ हिंदुओं की दुर्दशा की कहानी दर्शाती है, समाज के सभी वर्गों में सराही और पसंद की गई है। यह एक ऐसे समाज के रूप में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जहां हम अधिक से अधिक भारतीयों को चर्चा करते हुए देख रहे हैं और आज हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं उसे स्वीकार कर रहे हैं। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों को सब कुछ छोड़ना पड़ा, जब कश्मीर "रालिव, गालिव, चालिव" (धर्म बदलो, कश्मीर छोड़ो या मरो) के नारों से गूंज उठा और आज भी भारत के कई हिस्सों में इसके होने की संभावना है। उदाहरण के लिए असम, जिसने भीषण जनसांख्यिकीय परिवर्तन देखे हैं, ने भी खतरे को पहचान लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद लोगों में जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार एवं पलायन को असम में उसके पुराने समुदायों द्वारा दोहराया नहीं जाए।

यह फिल्म इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 'कश्मीरियत' के दोहरे मानकों को उजागर करती है जो कि वर्तमान संदर्भ में कश्मीर घाटी में सांप्रदायिक सद्भाव और धार्मिक समन्वय की सदियों पुरानी स्वदेशी परंपरा है। पिछले दशकों में पश्चिम देशों को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से ऐसी जानकारी दी गई है जो कश्मीर में भारत की भूमिका की एक विपरीत तस्वीर प्रस्तुत करती है। यह फिल्म कश्मीर की कहानी, भारत के पक्ष को पेश करने के लिए सॉफ्ट-पावर' के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करने के साधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। परिणाम यह है कि अमेरिका में 'रोड आइलैंड' राज्य ने आधिकारिक तौर पर कश्मीरी हिंदू जन-संहार को सदन के अध्यक्ष और प्रतिनिधि सभा के बहुमत और अल्पसंख्यक नेताओं ने स्वीकारा है।

अंत में, यह कहना झूठ नहीं होगा कि कश्मीर फाइल्स ने नवोदित फिल्म निर्माताओं के लिए अवसरों का पिटारा खोल दिया है, जो सामाजिक मुद्दे पर आधारित फिल्में बनाना चाहते हैं और बॉलीवुड में कहानी सुनाने का एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी तरीका भी स्थापित करना चाहते हैं। बॉलीवुड को कई दशकों से संवेदनशील और राजनीतिक मुद्दों से दूर रहने के लिए जाना जाता था, जिसके कारण हिंदुओं को कई कारणों से पीड़ित होना पड़ा है, जिसमें अंडरवर्ल्ड फंडिंग के प्रभाव से 'लेफ्ट लिबरल' द्वारा इन विषयों का प्रतिरोध तक शामिल हैं। हालांकि, कश्मीर फाइल्स को मिली अपार सफलता के साथ और जैसाकि हम देखते हैं कि बॉलीवुड में बड़े नाम भी धीरे-धीरे फिल्म के समर्थन में आ रहे हैं, उम्मीद है कि बॉलीवुड में एक ऐसा ईको-सिस्टम विकसित होगा जो किसी भी विषय के दूसरे पक्ष को भी प्रस्तुत करेगा।

भारत के बारे में नकारात्मक बातें करने वाले और पंडितों के जनसंहार जैसे घिनौने सच को दबाने की साजिश रचनेवालों की देर से लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि वे जानते हैं कि देश बदल गया है। यह अब उनके कुप्रचार द्वारा आत्ममुग्धता में डूबने को तैयार नहीं है और इसने हमारे इतिहास के तथ्यों का सामना करने के लिए विवेक विकसित कर लिया है। अब ये वामपंथी इतिहासकारों की जकड़ से मुक्त होना चाहते हैं।

यह बॉलीवुड और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब और अधिक दबी हुई सच्चाइयों के सामने आने की आशा है। ■

'बंगाल' हिंसा, बूथ-कैप्चरिंग और उत्पीड़न का शिकार

डॉ. अनिर्बान गांगुली
सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भाजपा
निदेशक, एसपीएमआरएफ

पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों में हिंसा, बूथ-कैप्चरिंग और आम मतदाताओं सहित विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को डराने एवं धमकाने की घटनाओं को देखा गया। टीएमसी की हमला करने और व्यवधान की रणनीति का खामियाजा सबसे ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं एवं उसके समर्थकों ने भुगता है। अदालतों में भाजपा की यह दलील कि नगर निगम चुनाव सीएपीएफ की निगरानी में कराए जाएं, को नकार दिया गया।

न्यायालयों ने राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) में यह कहते हुए अपना विश्वास व्यक्त किया था कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से स्थानीय चुनाव कराना संविधान द्वारा प्रदत्त एसईसी की जिम्मेदारी है और इसलिए इसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अदालतों को दिया गया एसईसी का आश्वासन महज एक दिखावा था। चुनाव कराने में राज्य चुनाव आयुक्त का पिछला रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है और इस बार भी चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसईसी की संवैधानिक शक्तियों को लागू करने में वह अक्षम और अनिच्छुक नजर आए।

इस बार भी उनका प्रदर्शन कुछ अलग नहीं था। वह पूरी तरह से अक्षम नजर आये और राज्य चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के दबाव में काम करते हुए देखा गया। एसईसी को बार-बार इस बात से अवगत करवाया गया कि भाजपा उम्मीदवारों को परेशान किया जा रहा है, प्रचार से रोका जा रहा है, उनके पोस्टर और पार्टी के झंडे को टीएमसी की हिंसक ब्रिगेड नष्ट किया जा रहा है, लेकिन इन सभी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। सत्ताधारी दल के दबाव में एसईसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और स्थिति को लगातार खराब होने दिया गया। कई मामलों में टीएमसी और टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने भाजपा उम्मीदवारों पर अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के लिए दबाव डाला और उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया। इसलिए, कई स्थानीय निकायों में टीएमसी को बिना किसी विरोध के सफलता हासिल हुई।

> मतदान के दिन कई लोगों को मतदान केंद्र पहुंचने पर पता चला कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है, कुछ को वापस लौटा दिया गया और अन्य बिना मतदान किये वापस जाने को मजबूर थे। यह हालात उस वक्त देखने को मिले जब टीएमसी के सशस्त्र गुंडों ने मतदान केंद्रों को अपने कब्जे में लेना आरंभ किया। इस दौरान अन्य दलों के बूथ एजेंटों पर हमला किया गया और मतदान अधिकारियों को भी केंद्रों से बाहर निकाल दिया गया

मतदान से एक दिन पूर्व टीएमसी ने राज्य भर में अपनी मशीनरी का उपयोग करते हुए अपने सशस्त्र गुंडों को तैनात कर दिया। इन दस्तों को विभिन्न इलाके में देखा गया, लेकिन सूचना दिये जाने के बाद भी पुलिस मूकदर्शक बनी रही और इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। इन असामाजिक तत्वों ने राज्य भर में कई वारदातों को अंजाम दिया, जैसाकि कोन्नगर, हुगली में भाजपा की वरिष्ठ नेता कृष्णा भट्टाचार्य के मामले में देखा गया। भट्टाचार्य को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन घर लौटते समय इन असामाजिक तत्वों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। यह हमले विशेष तौर पर सक्रिय एवं लोकप्रिय भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अंजाम दिये गये और इस तरह के बेहद हिंसक राजनीतिक माहौल में चुनावों को संपन्न करवाया गया।

मतदान के दिन कई लोगों को मतदान केंद्र पहुंचने पर पता चला कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है, कुछ को वापस लौटा दिया गया और अन्य बिना मतदान किये वापस जाने को मजबूर थे। यह हालात उस वक्त देखने को मिले जब टीएमसी के सशस्त्र गुंडों ने मतदान केंद्रों को अपने कब्जे में लेना आरंभ किया। इस दौरान अन्य दलों के बूथ एजेंटों पर हमला किया गया और मतदान अधिकारियों को भी केंद्रों से बाहर निकाल दिया गया। भाजपा बूथ एजेंटों को बूथों से दूर कर दिया गया। टीएमसी का संरक्षण प्राप्त इन बाहरी उपद्रवी तत्वों ने सभी बूथों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। ये गुंडे कभी हवा में बंदूक लहराते और कभी फायरिंग करते भी नजर आये। वास्तविकता यह है कि मतदान केंद्रों के सामने कोई कतार नहीं थी और फिर भी एसईसी ने दावा किया कि इन चुनावों में अस्सी प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ और 'कुल मिलाकर' मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा।

ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की हिमायती होने का दिखावा तो किया, लेकिन इन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और पश्चिम बंगाल में अब तक के सबसे अधिक हिंसा स्थानीय निकाय चुनावों में से

एक को संपन्न करवाया। पश्चिम बंगाल नगर निकाय चुनाव दो पड़ोसी राज्यों— असम और त्रिपुरा में हुए स्थानीय निकाय चुनावों से बिल्कुल विपरीत थे, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे। यह स्पष्ट है कि केवल भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा कर सकती हैं और इसकी भावना को संरक्षित करने के साथ संवैधानिक ढांचे की रक्षा भी कर सकती हैं। वाम मोर्चा और और अब टीएमसी सरकारों के शासन ने पश्चिम बंगाल के लोकतंत्रिक ढांचे पर बार-बार अघात करने का काम किया है। ममता बनर्जी ने जनता के बीच से उठने वाली लोकतांत्रिक आवाज को बार-बार दबाने का काम किया है, उन्होंने बार-बार जनता को उनके अधिकारों का उपयोग करने से रोका है और हाल ही में संपन्न स्थानीय निकायों के चुनाव इसका नवीनतम उदाहरण है। यह चुनावी प्रक्रिया उसकी असहिष्णुता को दर्शाती है।

इन हिंसक घटनाओं पर कोई खेद व्यक्त करने के बजाय ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि यह चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए और यह आम जनता की राय को दर्शाते हैं। इन चुनावों के परिमाण जब आये तो यह स्पष्ट हो गया था कि जनादेश लोगों का नहीं था, बल्कि टीएमसी की दादागिरी का परिणाम थे। जो धर्मनिरपेक्ष उदारवादी श्री नरेन्द्र मोदी के शासन में भारत के 'बिगड़ते' लोकतांत्रिक मूल्यों जैसी काल्पनीक बातों को लेकर चिंता जाहिर करते है, वही ममता बनर्जी द्वारा लोकतंत्र की हत्या पर मौन बैठे हैं। शायद ही किसी अखबार का संपादकीय इसको लेकर लिखा गया है, ऐसे ही बहुत कम स्तंभकारों ने इस घटना का जिक्र अपनी लेखनी में किया और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यधारा के मीडिया ने भी इन घटनाक्रम को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए इससे ममता बनर्जी में लोगों के विश्वास की 'जीत' बताया है।

हाल ही में बीरभूम जिले में रामपुरहाट में सामूहिक हत्याकंड हुआ, जिसमें टीएमसी के दो गुटों ने एक-दूसरे पर हमला किया। इस घटना में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया और स्थानीय लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें उनकी निर्मम हत्या हुई। इस घटना ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुःखद घटना पर चिंता व्यक्त की और जनता को ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों को नहीं बख्शने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि कैसे एक सप्ताह से अधिक समय के दौरान पश्चिम बंगाल में 26 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। इन घटनाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भी हत्या की गयी, जो यह दर्शाता है कि तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद टीएमसी अहंकार से भरी हुई है। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि राज्य में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी निष्प्रभावी कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं और उनके सशस्त्र और हिंसक गुटों पर लगाम लगाने का कोई प्रयास नहीं किया है। यह पश्चिम बंगाल को भय और हिंसा की गिरफ्त में रखने के लिए उसकी रणनीति का हिस्सा है, जिससे स्थानीय लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और इच्छाशक्ति को दबाकर उन पर एकछत्र शासन किया जा सके। रामपुरहाट नरसंहार हाल की राजनीतिक हत्याओं के इतिहास में से सबसे क्रूर घटना है।

> **हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों और चार राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने इस अलोकतांत्रिक और हिंसक मानसिकता को गंभीर चुनौती दी है। टीएमसी की राजनीति और लोकतंत्र को लेकर उसके बनावटी चेहरे का पर्दाफाश हो चुका है। उम्मीद है कि समय के साथ पश्चिम बंगाल के लोग भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के 'नए भारत' के दृष्टिकोण के लिए अपनी वास्तविक लोकतांत्रिक पसंद और वरीयता का प्रयोग करने में सक्षम होंगे**

यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत का लोकतांत्रिक वर्तमान और भविष्य भाजपा के पास ही सुरक्षित है। भाजपा द्वारा शासित प्रत्येक राज्य ने एक नया शासन प्रतिमान और ढांचा पेश किया है। सुशासन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर अधिक से अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की पहचान बन गया है। यह एक बढ़ती हुई वैश्विक स्वीकृति है कि भारत सभी मानकों पर बदल रहा है और प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में विश्व मंच पर एक प्रमुख लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भाजपा के राजनीतिक विरोधियों और उसके बौद्धिक सहयोगियों के पास इसका मुकाबला करने के लिए कोई मॉडल, कोई योजना, कोई आख्यान नहीं है। उनका एकमात्र कार्य प्रधानमंत्री श्री मोदी को लेकर कुप्रचार करना और एक हिंसक राजनीतिक एजेंडा चलाना है जिसका उद्देश्य मतदाताओं को किसी एक तरफ वोट देने के लिए बाध्य करना है, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों और चार राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने इस अलोकतांत्रिक और हिंसक मानसिकता को गंभीर चुनौती दी है। टीएमसी की राजनीति और लोकतंत्र को लेकर उसके बनावटी चेहरे का पर्दाफाश हो चुका है। उम्मीद है कि समय के साथ पश्चिम बंगाल के लोग भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के 'नए भारत' के दृष्टिकोण के लिए अपनी वास्तविक लोकतांत्रिक पसंद और वरीयता का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। ■

ऑपरेशन गंगा: भारत के सबसे लंबे निकासी अभियान में से एक

विजय चौथाईवाले
प्रभारी, विदेश मामले विभाग
भाजपा

'ऑपरेशन गंगा' भारत के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक है, जिसे ऑपरेशन 'देवी शक्ति' के बाद विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया था। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के दौरान ऑपरेशन 'देवी शक्ति' शुरू किया गया था। और अब 'ऑपरेशन गंगा' के तहत युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे लगभग 22,500 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया, जो एक सराहनीय कार्य है। भारत न केवल 'ऑपरेशन गंगा' के माध्यम से भारतीय नागरिकों को निकालने में सफल रहा, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के नागरिकों को उनके देशों तक सुरक्षित पहुंचाने में भी मदद की। भारत ने रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा से अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला। दरअसल इन देशों तक यूक्रेन में फंसे भारतीय सड़क और रेल मार्ग से पहुंचे थे। यह ऑपरेशन फरवरी, 2022 में शुरू हुआ और 10 मार्च तक लगभग 80 उड़ानों के माध्यम से भारतीयों को निकाला गया। प्रारंभ में नागरिक एयरलाइनों का उपयोग निकासी प्रक्रिया के लिए किया गया, लेकिन जैसे-जैसे स्थिति बदली, भारतीय वायु सेना को भी इस कार्रवाई में शामिल किया गया। सिविल एयरलाइंस के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को निकालना संभव नहीं था और इसलिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारतीय वायुसेना को इस ऑपरेशन में शामिल किया गया। इसके लिए सी-17 ग्लोबमास्टर को ऑपरेशन में लगाया गया, जो एक बार मे 400 यात्रियों को लेकर उड़ान भर सकता है। सी-17 ने न केवल यूक्रेन से लोगों को भारत वापस लाने में मदद की, बल्कि मानवीय सहायता के तौर पर भोजन, ईंधन, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुओं को यूक्रेन तक भी पहुंचाया।

पहले भी कई मौकों पर भारत एक ऐसा देश साबित हुआ है जो मुश्किल समय में अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहा है। इससे पहले 1990 में पहली बार किसी निकासी अभियान को अंजाम दिया गया था, जिसमें कुवैत में फंसे 1,70,000 से अधिक भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। 2006 में ऑपरेशन 'सुकून' ने लेबनान और इज़राइल संघर्ष के दौरान श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों सहित 2,280 लोगों को निकाला। 2011 में ऑपरेशन 'सुरक्षित घर वापसी' के तहत संघर्षग्रस्त लीबिया से लगभग 15,400 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकाला था। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह के अभियानों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार भारत की सराहना हुई है। 2015 में भारत ने यमन और हैती विद्रोहियों के बीच संघर्ष के दौरान हजारों भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन 'राहत' की शुरुआत की। 2016 में 28 क्रू सदस्यों सहित 242 भारतीयों को आतंकवादी हमलों के दौरान ब्रसेल्स से सफलतापूर्वक एयरलिफ्ट किया गया था। समुद्र मार्ग से कोविड महामारी के दौरान 3992 नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए वर्ष 2020 में ऑपरेशन 'समुद्र सेतु' शुरू किया गया था। कोविड प्रभावित देशों से भारतीयों को निकालने के लिए 'वंदे भारत मिशन' वर्ष 2020 में शुरू किया गया था और इसके माध्यम से कई चरणों में 60 लाख से अधिक भारतीयों को निकाला गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान 'ऑपरेशन गंगा' के तहत भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए 80 उड़ानें भरी गयीं, जिसमें से करीब 46 निजी एयरलाइंस द्वारा संचालित थीं। इन उड़ानों में 29 बुखारेस्ट रोमानिया, 10 बुडापेस्ट हंगरी, छह रेज़ज़ो पोलैंड और एक कोकिस स्लोवाकिया से संचालित की गयी। सभी नागरिकों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से निःशुल्क भारत लाया गया, जिसके लिए भारत सरकार को प्रति उड़ान 66-70 करोड़ रुपये का खर्च होने की उम्मीद है।

भारतीय नागरिकों और भारत सरकार के बीच आवश्यक संवाद सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण केंद्र स्थापित किया। जिसके माध्यम से प्राप्त प्रत्येक 'पूछताछ' को डेटाबेस में सत्यापित किया गया और उन्हें आवश्यक राहत योजना से अवगत कराया गया। इस दौरान भारत की कूटनीति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण पूर्वी यूरोप के पड़ोसी देशों ने भारतीय नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान की। उदाहरण के लिए पोलैंड ने अपनी सीमाओं में प्रवेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को माफ कर दिया।

उधर रुस-यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीयों की निकासी को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया। उन्होंने कई पड़ोसी देशों के मंत्रियों, नौकरशाहों, भारतीय दूतावासों और सरकारों को इसमें शामिल किया और विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकों के माध्यम से पूरी

स्थिति की निगरानी की। इस प्रक्रिया को तेज करने और भारतीय नागरिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए चार भारतीय कैबिनेट मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू को स्लोवाक गणराज्य, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी को हंगरी और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) श्री वीके सिंह को ऑपरेशन गंगा के तहत पोलैंड भेजा गया।

जैसे-जैसे संघर्ष तेज होता गया, असली चुनौती उन भारतीयों को निकालने की थी, जो पूर्वी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत ने यूक्रेन और रूस के साथ अपनी चर्चा में लोगों को युद्ध क्षेत्रों से दूर जाने की सुविधा के लिए मानवीय मार्ग बनाने का सुझाव दिया था। अब चीजें अधिक जटिल हो रही थीं, क्योंकि यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद हो गया था और इसलिए कीव और खार्किव जैसे शहरों से सीधे निकासी असंभव हो गई थी। ऐसे में लोगों को निकटतम सीमाओं पर जाने का सुझाव देते हुए सलाह जारी की गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से युद्धविराम कर, युद्ध प्रभावित क्षेत्र से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए बात की। उदाहरण के लिए सुमी में फंसे 694 छात्र श्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर बनाये गये मानवीय गलियारों के माध्यम से पोल्टावा जाने में सक्षम हुए।

इस आपरेशन में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी एक प्रमुख भूमिका निभाई गई। सेवा इंटरनेशनल, इस्कॉन, आर्ट ऑफ लिविंग, बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था, कई गुरुद्वारों, पोलैंड और हंगरी जैसे पड़ोसी देशों में हिंदू मंदिरों के संगठनों ने संघर्ष से प्रभावित लोगों को आश्रय और भोजन प्रदान किया। जान गंवाने वाले लोगों के लिए दुनिया भर के कई मंदिरों में प्रार्थना की गई और युद्ध को जल्द से जल्द बंद करने के लिए भी प्रार्थना की गई।

रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के दौरान भारत की रणनीतिक तटस्थता की वैश्विक स्तर पर सराहना की गई है। भारत ने हिंसा की निंदा की और यूक्रेन को आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान की। आम लोगों की सुरक्षित आवाजाही के लिए दोनों देशों के साथ बातचीत की और किसी का भी पक्ष नहीं लिया, भारत के इस रुख ने हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक लिहाज से काफी कुछ हासिल किया है। चाहे 2015 में नेपाल भूकंप के दौरान निकासी हो या 2022 का यूक्रेन संकट, भारत ने कई अभियानों के माध्यम से न केवल अपने नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाला है, बल्कि अन्य राष्ट्र के नागरिकों को सभी सुरक्षित निकालने में मदद की है। देखा जाए तो दुनिया भर में भारतीय मूल के अप्रवासी फैले हुए है, तो ऐसी स्थितियों का सामना भविष्य में भी किया जा सकता है। ऐसे में 'ऑपरेशन गंगा' की सफलता से भारतीयों में यह विश्वास पैदा हुआ है कि चाहे वे कहीं भी हों, उनकी सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता में है। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक मित्र राष्ट्र के रूप में अपनी छवि विकसित की है जो हमेशा अपने प्रवासी के साथ खड़ा रहा है और संकट की स्थिति के दौरान अन्य देशों के लोगों की भी मदद करता आया है। इस ऑपरेशन में शामिल हितधारक भारत सरकार, अधिकारी, एयरलाइन कंपनियां और उनके कर्मचारी, भारतीय वायु सेना और वे नागरिक एवं उनके परिवार जिन्होंने धैर्यपूर्वक प्रक्रियाओं का समर्थन और पालन किया, उन सभी को इस आपरेशन की सफलता का श्रेय दिया जाना चाहिए। ■

अति आधुनिक 'ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल' इलेक्ट्रिक व्हीकल का शुभारंभ

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 16 मार्च को नई दिल्ली में दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) टोयोटा मिराई का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री श्री आरके सिंह, केंद्रीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर लिमिटेड के एमडी श्री मसाकाजू योशिमुरा, टीकेएम लिमिटेड के वीसी श्री विक्रम किर्लोस्कर और अधिकारी भी उपस्थित थे।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी) दुनिया के सबसे उन्नत फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफसीईवी) टोयोटा मिराई का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का संचालन कर रहे हैं जो भारतीय सड़कों और जलवायु परिस्थितियों में हाइड्रोजन पर चलता है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन और एफसीईवी प्रौद्योगिकी की अनूठी उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करके देश में एक ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इकोसिस्टम बनाना है।

यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा

और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी और इस तरह 2047 तक भारत को 'ऊर्जा आत्मनिर्भर' बनाएगी। हाइड्रोजन द्वारा संचालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (एफसीईवी) सबसे अच्छे शून्य उत्सर्जन समाधानों में से एक है। यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है जिसमें पानी के अलावा कोई अन्य उत्सर्जन नहीं है। ■

मीडिया ने योग, फिटनेस और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' को लोकप्रिय बनाने में बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई: नरेन्द्र मोदी

भारत के प्रतिभाशाली युवाओं की शक्ति से हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रयासों का मार्गदर्शक सिद्धांत है— आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्तमान की तुलना में बेहतर जीवन-शैली सुनिश्चित हो

गत 18 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मातृभूमि के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अखबार की यात्रा में शामिल सभी प्रमुख हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों की प्रेरणा से मातृभूमि की स्थापना भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए हुई थी। उन्होंने हमारे देश के लोगों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुट करने के लिए पूरे भारत में स्थापित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की गौरवशाली परंपरा में इस अखबार को भी स्थान दिया।

श्री मोदी ने लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, श्यामजी कृष्ण वर्मा और अन्य लोगों का उदाहरण दिया, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने कार्यों के लिए अखबार का उपयोग किया। आपातकाल के दौरान भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए उन्होंने श्री एम.पी. वीरेंद्र कुमार के प्रयासों को विशेष रूप से याद किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वराज्य के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमें अपने जीवन का बलिदान करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन यह अमृत काल हमें एक मजबूत, विकसित और समावेशी भारत की दिशा में काम करने का अवसर देता है। उन्होंने 'न्यू इंडिया' के अभियानों पर मीडिया के सकारात्मक प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया।

श्री मोदी ने 'स्वच्छ भारत मिशन' का उदाहरण दिया, जहां हर मीडिया हाउस ने इस मिशन को बड़ी गंभीरता से लिया। इसी तरह योग, फिटनेस और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि ये राजनीति और राजनीतिक दलों के क्षेत्र से बाहर के विषय हैं। ये आने वाले वर्षों में एक बेहतर राष्ट्र बनाने के बारे में हैं।

श्री मोदी ने सुझाव दिया कि मीडिया; स्वतंत्रता संग्राम की अल्प-ज्ञात घटनाओं, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों एवं संघर्ष से जुड़े स्थानों को उजागर करने के प्रयासों को बढ़ावा दे सकता है। इसी तरह, समाचार पत्र गैर-मीडिया पृष्ठभूमि के लेखकों को मंच देने और उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका हो सकता है, जहां वे नहीं बोली जाती हैं।

दो साल तक 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिला

वर्तमान समय में भारत से दुनिया की अपेक्षाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने महामारी से निपटने में असमर्थता की प्रारंभिक अटकलों को खारिज कर दिया। दो साल तक 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिला। वैक्सीन की 180 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवाओं की शक्ति से हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस सिद्धांत के मूल में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है, जो घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो।

श्री मोदी ने कहा कि अभूतपूर्व सुधार किये गए हैं, जिनसे आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गईं हैं। उन्होंने कहा कि भारत का स्टार्ट-अप इकोसिस्टम कभी भी इतना अधिक जीवंत नहीं रहा है। पिछले 4 वर्षों में यूपीआई लेनदेन की संख्या 70 गुना से अधिक बढ़ गई है।

श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर 110 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गतिशक्ति, बुनियादी ढांचे और शासन को और अधिक सहज बनायेगी। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं कि भारत के हर गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। हमारे प्रयासों का मार्गदर्शक सिद्धांत है— आने वाली पीढ़ियों के लिए वर्तमान की तुलना में बेहतर जीवन शैली सुनिश्चित हो। ■

भारत-जापान के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर

कोविड काल के बाद एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व के लिए साझेदारी

जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 19 मार्च से 20 मार्च, 2022 के दौरान एक आधिकारिक दौरे पर भारत आए। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यह स्वीकार किया कि यह शिखर बैठक एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हो रही है जब दोनों देश अपने द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 19 मार्च को अपने जापानी समकक्ष श्री किशिदा के साथ आर्थिक, कारोबारी एवं ऊर्जा क्षेत्र सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर बातचीत की और दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए। ये समझौते साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचा विकास और शहरी विकास से संबंधित हैं। गौरतलब है कि जापान ने भारत में 3,20,000 करोड़ रुपये के निवेश लक्ष्य की घोषणा की।

भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को दोहराते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 2018 में जारी किए गए भारत-जापान दृष्टिकोण वक्तव्य में प्रतिपादित साझा मूल्य और सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक हैं, जहां बेहद गंभीर हो चुकी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक सहयोग की जरूरत पहले से कहीं अधिक है।

उन्होंने राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने वाली एक नियम-आधारित व्यवस्था की नींव पर टिके एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व की दिशा में मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और सभी देशों द्वारा धमकी या बल प्रयोग या यथास्थिति को एकतरफा बदलने के किसी भी प्रयास का सहारा लिए बिना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर बल दिया। इस संबंध में उन्होंने जोर-जबरदस्ती से मुक्त, स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपने साझा दृष्टिकोण को दोहराया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निकटता के साथ सहयोग करने के अपने इरादों को दोहराया और मानवीय संकट को दूर करने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और एक वास्तविक प्रतिनिधिक एवं समावेशी राजनीतिक प्रणाली की स्थापना सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की

दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर गहरी चिंता व्यक्त की और आतंकवाद का व्यापक तरीके से एवं निरंतर मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित किया। उन्होंने सभी देशों से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों एवं बुनियादी ढांचे को खत्म करने, आतंकवादी नेटवर्क और उनके वित्तपोषण के चैनलों को अवरुद्ध करने और आतंकवादियों की सीमा पार से आवाजाही को रोकने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस संदर्भ में उन्होंने सभी देशों से उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादी हमले के लिए न होने देने और इस तरह के हमलों के अपराधियों को शीघ्रता से दंडित करने का भी आह्वान किया।

उन्होंने 26/11 मुंबई और पठानकोट हमलों सहित भारत में आतंकवादी हमलों की फिर से निंदा की और पाकिस्तान से अपनी जमीन से संचालित होने वाले आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ दृढ़ और अचूक कार्रवाई करने और एफएटीएफ सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पूरी तरह से पालन करने का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता (सीसीआईटी) को शीघ्र अपनाने की दिशा में मिलकर काम करने पर भी सहमति व्यक्त की।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात की खुशी व्यक्त की कि द्विपक्षीय संबंधों के एक विशेष सामरिक एवं वैश्विक भागीदारी में बदलने के बाद से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए जापान द्वारा की गई विभिन्न पहलों की सराहना की। इस संदर्भ में दोनों प्रधानमंत्रियों ने नवंबर, 2021 में भारत-जापान

औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी (आईजेआईसीपी) की स्थापना को याद किया और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम), विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों सहित दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए आईजेआईसीपी के तहत एक रोडमैप तैयार किए जाने का स्वागत किया।

उन्होंने 75 बिलियन अमरीकी डालर के अपने द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौते के नवीनीकरण का स्वागत किया।

बैठक के बाद मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत-जापान भागीदारी को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी शांति, समृद्धि और स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री मोदी ने कहा कि देश में समर्पित माल ढुलाई (फ्रेट) गलियारा और मुम्बई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस योगदान के लिए आभारी हैं। मुम्बई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है।

श्री मोदी ने कहा कि आज भारत 'दुनिया के लिये मेक इन इंडिया (मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड)' के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है और इस संदर्भ में जापानी कंपनियां बहुत समय से एक प्रकार से हमारी ब्रांड राजदूत रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा स्वच्छ ऊर्जा गठजोड़ इस दिशा में लिया गया, एक निर्णायक कदम साबित होगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान, दोनों ही सुरक्षित, भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति के महत्व को समझते हैं तथा यह टिकाऊ आर्थिक विकास के लक्ष्य को पाने और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए अनिवार्य है। ■

भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा के साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन ने 21 मार्च को भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरा वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं वैश्विक विकास के बारे में विचारों का आदान-प्रदान किया।

शिखर सम्मेलन की शुरुआत में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में भीषण बाढ़ के कारण हुई तबाही और इसके परिणामस्वरूप हुई जानमाल की क्षति पर अपनी संवेदना व्यक्त की।

दोनों नेताओं ने जून, 2020 में पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आपसी संबंधों के बढ़ते हुए दायरे पर संतोष व्यक्त किया। संबंधों के इस बढ़ते हुए दायरे में अब व्यापार एवं निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा, शिक्षा एवं नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों, जल प्रबंधन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, कोविड-19 से संबंधित अनुसंधान आदि जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री स्कॉट मॉरिसन को 29 प्राचीन कलाकृतियों को भारत को लौटाने की विशेष पहल के लिए धन्यवाद दिया। इन कलाकृतियों में सदियों पुरानी मूर्तियां, चित्रकला एवं तस्वीरें शामिल हैं, जिनमें से कई 9वीं-10वीं शताब्दी की हैं और उनका संबंध भारत के विभिन्न हिस्सों से है। इन कलाकृतियों में 12वीं सदी के चोल कांस्य, राजस्थान की 11वीं-12वीं सदी की जैन मूर्तियां, गुजरात की 12वीं-13वीं सदी की बलुआ पत्थर से निर्मित देवी महिषासुरमर्दिनी, 18वीं-19वीं सदी की चित्रकारी और शुरुआती दौर की जिलेटिन चांदी की तस्वीरें शामिल हैं।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों सहित भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मॉरिसन को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने साझे मूल्यों और समान हितों वाले सहयोगी लोकतंत्र के रूप में दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक जुड़ाव की भी सराहना की, जिसमें एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध भारत–प्रशांत क्षेत्र शामिल है।

इस अवसर पर गहन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दोनों पक्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर बैठक आयोजित करने पर भी सहमत हुए और इस प्रकार द्विपक्षीय संबंधों में एक विशेष आयाम जुड़ गया। ■

गुजरात के लोगों ने सहकारिता का चमत्कार देखा है: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 मार्च को गुजरात के सूरत में सुमुल डेयरी की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्रीमती दर्शन जरदोश और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज दक्षिण गुजरात के तापी जिले में ऐतिहासिक सहयोग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति और उत्साह इस बात का प्रमाण है कि गुजरात में सहकारी ढांचा कितना मजबूत है।

श्री शाह ने कहा कि यह देश की आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। भारत की आजादी को 75 वर्ष बीत चुके हैं और आजादी का 75वां वर्ष किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर विषय को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष को राष्ट्र के लिए संकल्प के वर्ष के रूप में मनाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह देश के हर क्षेत्र में संकल्प लेने का वर्ष है कि स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के बाद देश किन ऊंचाइयों पर होगा। प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ लोगों से आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को एक संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया है।

श्री शाह ने कहा कि चाहे वह देश की सुरक्षा का विषय हो या देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का विषय हो, चाहे नई शिक्षा नीति के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन लाना हो, देश के सूक्ष्म व्यवसायों को समृद्ध बनाना हो, स्वयं सहायता समूहों और प्रत्येक नागरिक को समृद्ध बनाना हो या देश के युवाओं को विश्व पटल पर स्थापित करना हो, प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र में भारत को दुनिया में सबसे अग्रणी रखने का प्रयास किया है। हमारा लक्ष्य सभी सहकारी समितियों के कार्यकर्ताओं के लिए सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में इसे विश्व का सबसे मजबूत सहकारी आंदोलन बनाना है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि 71 वर्ष पहले प्रारंभ हुई सुमूल की यात्रा 200 लीटर से शुरू होकर आज 20 लाख लीटर तक पहुंची है, जिसमें दूध उत्पादक जनजातीय पुरुषों और महिलाओं का बहुत योगदान है। आज जनजातीय महिलाओं की कड़ी मेहनत और लगन के दम पर रोजाना 7 करोड़ रुपये के दूध की बिक्री होती है और 2.5 लाख सदस्यों के बैंक खातों में सीधे 7 करोड़ रुपये हस्तांतरण करने की व्यवस्था की गई है।

71 वर्ष पहले प्रारंभ हुई सुमूल की यात्रा 200 लीटर से शुरू होकर आज 20 लाख लीटर तक पहुंची है, जिसमें दूध उत्पादक जनजातीय पुरुषों और महिलाओं का बहुत योगदान है। आज जनजातीय महिलाओं की कड़ी मेहनत और लगन के दम पर रोजाना 7 करोड़ रुपये के दूध की बिक्री होती है और 2.5 लाख सदस्यों के बैंक खातों में सीधे 7 करोड़ रुपये हस्तांतरण करने की व्यवस्था की गई है

सहकारिता आंदोलन से जनजातीय महिलाओं में समृद्धि

श्री शाह ने कहा कि कौन सोच सकता है कि एक से दो एकड़ जमीन पर खेती करने वाली जनजातीय महिलाओं के बैंक खाते में हर दिन पैसा जमा होता है। यह सहकारिता के सिद्धांत का चमत्कार है, सहकारिता आंदोलन का चमत्कार है। यह एक सहकारी प्रणाली का चमत्कार है जो गुजरात में और अमूल के तत्वावधान में श्री त्रिभुवन पटेल के प्रयास और शक्ति द्वारा स्थापित किया गया है।

उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि 2022 आजादी की 75वीं वर्षगांठ होगी और हमें 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। आज मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने उस दिशा में बहुत से कार्य किये हैं। कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली से हर वर्ष 13 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे 6,000 रुपये भेजे

हैं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र में कार्यरत कई प्राथमिक कृषि समितियों, दुग्ध उत्पादक संघों, एपीएमसी, मछुआरे भाइयों के संघों, ट्रेड यूनियनों, छोटे औद्योगिक संघों की स्थापना की है। श्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। सहकारिता आंदोलन से जुड़े पुरुषों और महिलाओं एवं यहां उपस्थित सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के फैसले के लिए आओ हम तालियों की गड़गड़ाहट से श्री मोदी का धन्यवाद करें।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि गुजरात के लोगों ने सहकारिता का चमत्कार देखा है। सरदार पटेल, त्रिभुवन भाई, भाई काका, वैकुंठभाई मेहता ने गुजरात में एक मजबूत सहकारी आंदोलन की नींव रखी और आज अमूल उस नींव पर खड़ा है। अमूल का ब्रांड 53,000 करोड़ रुपयों के कारोबार के साथ एक वैश्विक ब्रांड बन गया है, जो सहकारिता आंदोलन की ताकत को दर्शाता है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता क्षेत्र के लिए बजट में कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। चीनी मिलों से जुड़े लोग 40 वर्ष से आयकर और 8,000 करोड़ रुपये की देनदारी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा तुरंत समाप्त कर दिया गया। उन्होंने सभी सहकारी उत्पादन संस्थानों के उद्योग कर को समान कर दिया।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार आगामी दिनों में सभी प्राथमिक कृषि समितियों को सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। 900 करोड़ रुपयों से अधिक के बजट के साथ नरेन्द्र मोदी सरकार ने मूलभूत सुविधाओं के लिए सहकारिता विभाग का गठन किया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना है और आगामी दिनों में सहकारिता क्षेत्र इसमें सबसे ज्यादा योगदान देगा।

उन्होंने कहा कि जब सहकारी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है, उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ता है तो लाखों करोड़ों लोगों को लाभ होता है। अगर सुमूल समृद्ध है तो 2.5 लाख लोगों को लाभ होगा और अगर निजी डेयरी मजबूत होगी तो सिर्फ पांच लोगों को ही लाभ होगा। अगर सहकारी क्षेत्र मजबूत होगा तो गरीब आदमी मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, देश की पशुचारक महिलाएं मजबूत होंगी।

मोदीजी का प्राकृतिक कृषि पर बहुत जोर

श्री शाह ने कहा कि श्री मोदी ने प्राकृतिक कृषि पर बहुत जोर दिया है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। प्राकृतिक कृषि से न केवल भूमि की उर्वरता में सुधार होगा, लोगों का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह जैसे रोगों से प्रभावित नहीं होंगे। आज जब आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि प्राकृतिक कृषि ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्राकृतिक कृषि में लगे किसानों की आय बढ़ाने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय, श्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और गुजरात सरकार की भी है।

उन्होंने कहा कि अमूल के तत्वावधान में जैविक कृषि के उत्पाद को अच्छी कीमत दिलाने के लिए एक तंत्र शुरू किया गया है। उत्पाद की विश्वसनीयता, वैज्ञानिक परीक्षण, गुणवत्ता, प्रमाणन, विपणन के लिए विश्व बाजार में अपना माल बेचना, यह सब करना है; तो पूरा वैज्ञानिक ढांचा और शृंखला बनानी होगी और इसके लिए अमूल ने प्राथमिकता दर्शायी है। यह ढांचा एक वर्ष के भीतर तैयार किया जाएगा और इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राकृतिक कृषि में कार्य कर रहे किसानों को उनके उत्पादों का अच्छा दाम मिले।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वह गुजरात के किसानों से अपील करना चाहते हैं कि वह प्राकृतिक कृषि का अध्ययन करें, इसे जानें, इसे स्वीकार करें और इसे अपने खेतों में उपयोग में लाएं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में इस अभियान को चलाएं, इससे हम न केवल पृथ्वी और पर्यावरण की रक्षा करेंगे, बल्कि किसानों की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और इसके साथ ही 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य में सुधार की जिम्मेदारी भी हम पर है। हम लोगों को रसायन मुक्त खाद्यान्न, रसायन मुक्त भोजन, रसायन मुक्त फल, रसायन मुक्त सब्जियां उपलब्ध कराने में पूरी तरह सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि मोदीजी का समृद्ध और स्वस्थ भारत का स्वप्न शीघ्र ही साकार होगा। ■

आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र' के लिए मेजबान देश समझौते पर किए हस्ताक्षर

'वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केन्द्र' का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना और विश्व भर के समुदायों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना है

केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने गुजरात में आयुर्वेद में प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थित अपने अंतरिम कार्यालय के साथ गुजरात के जामनगर में भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए डब्ल्यूएचओ वैश्विक केन्द्र (जीसीटीएम) की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए।

इस केंद्र को भारत सरकार की ओर से लगभग 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश से सहायता मिलेगी। जीसीटीएम का प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना और विश्व भर के समुदायों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना है।

इस समझौते पर 25 मार्च, 2022 को जिनेवा में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस द्वारा हस्ताक्षर किए गए। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र की स्थापना को मंजूरी दी थी।

भारत की पारम्परिक औषधियां और स्वास्थ्य विधियां विश्व स्तर पर काफी लोकप्रिय हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को लेकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह केंद्र धरती को स्वस्थ बनाने और वैश्विक हित में हमारी समृद्ध पारम्परिक विधियों के दोहन करने में अपना योगदान देगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ के ट्वीट्स का उत्तर देते हुए यह बात कही।

प्रधानमंत्री ने 26 मार्च को ट्वीट करते हुए कहा कि भारत अपने यहां अत्याधुनिक डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को लेकर खासा सम्मानित महसूस कर रहा है। यह केंद्र एक स्वस्थ ग्रह के निर्माण और वैश्वित हित के लिए हमारी समृद्ध पारंपरिक विधियों के दोहन की दिशा में योगदान करेगा।

उन्होंने कहा कि भारत की पारम्परिक औषधियां और स्वास्थ्य विधियां विश्व स्तर पर काफी लोकप्रिय हैं। यह डब्ल्यूएचओ केंद्र हमारे समाज में खुशहाली फैलाने की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगा।

भारत सरकार की पहल के महत्व को रेखांकित करते हुए डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस ने कहा

कि आधुनिक विज्ञान और समानता तथा स्थिरता के सिद्धांतों पर चित्रण करके पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन 21वीं सदी में स्वास्थ्य के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव सिद्ध होगा।

जीसीटीएम विश्व भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केन्द्र (कार्यालय) होगा। यह पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और उत्पादों पर नीतियों और मानकों के लिए ठोस आधार साक्ष्य के निर्माण पर फोकस करेगा तथा देशों को उपयुक्त तरीके से इसे उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों में समेकित करने तथा इष्टतम और टिकाऊ प्रभाव के लिए इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा को विनियमित करने में सहायता करेगा।

पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ है और न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल के वर्ष में पारंपरिक चिकित्सा उपचारों में भी प्रमुख बदलाव देखा गया है क्योंकि कृत्रिम आसूचना, प्रौद्योगिकी नवोन्मेषणों के उपयोग ने इसे आम लोगों के लिए और अधिक सुलभ बना दिया है।

आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ कृत्रिम आसूचना (एआई) का उपयोग अब पारंपरिक चिकित्सा में साक्ष्य और रुझानों को मानचित्रित करने तथा फार्माकोकाइनेटिक गुणों के लिए प्राकृतिक उत्पादों की जांच करने के लिए किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ-जीसीटीएम की रूपरेखा विश्व के सभी क्षेत्रों को शामिल करने और लाभान्वित करने के लिए बनायी गई है। उल्लेखनीय है कि शिलान्यास समारोह 21 अप्रैल, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। ■

भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में 10 अंकों की भारी गिरावट

मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) जो 2016-18 में 113 था, वह 2017-19 में घटकर 103 हो गया जो 8.8 प्रतिशत गिरावट दर्शाता है

भारत के महापंजीयक द्वारा जारी किए गए विशेष बुलेटिन के अनुसार देश के मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में 10 अंकों की गिरावट अर्जित की गई, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एमएमआर जो 2016-18 में 113 था, वह 2017-19 में घटकर 103 हो गया जो 8.8 प्रतिशत गिरावट दर्शाता है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 14 मार्च को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार देश में एमएमआर में लगातार कमी आई है। यह 2014 से 2016 में 130 था, जो 2015 से 2017 में घटकर 122, 2016 से 2018 में कम होकर 113 और 2017 से 2019 में 103 रह गया।

इस लगातार गिरावट से भारत 2030 तक निश्चित रूप से 70 प्रति लाख जीवित जन्म के एसडीजी लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर है।

गौरतलब है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत रणनीतिक निवेश लगातार लाभांश सृजित कर रहा है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान और लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव (लक्ष्य) के तहत गुणवत्ता युक्त देखभाल प्रयासों तथा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना जैसी मौजूदा योजनाओं के संयोजन से महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किए गए हैं। ■

अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन की संचयी वृद्धि 14.2 प्रतिशत बढ़ी

जनवरी, 2022 (आधारः 2011-12 = 100) के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 124.7 पर, इसी अवधि के 2021 के स्तर की तुलना में 2.8 प्रतिशत अधिक था। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जनवरी 2021-22 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.2 प्रतिशत की संचयी वृद्धि हुई।

केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा 17 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार जनवरी, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर थाः कोयला 796 लाख टन, लिग्नाइट 46 लाख टन, प्राकृतिक गैस (प्रयुक्त) 2767 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम (कच्चा) 25 लाख टन, बॉक्साइट 2157 हजार टन, क्रोमाइट 398 हजार टन, कॉपर सांद्र 10 हजार टन, सोना 107 किलो, लौह अयस्क 215 लाख टन, सीसा सांद्र 29 हजार टन, मैगनीज अयस्क 264 हजार टन, जस्ता सांद्र 145 हजार टन, चूना पत्थर 341 लाख टन, फास्फोराइट 118 हजार टन, मैग्नेसाइट 10 हजार टन और हीरा 1 कैरेट।

जनवरी, 2021 की तुलना में जनवरी, 2022 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में शामिल हैंः मैग्नेसाइट (36.6 प्रतिशत), लिग्नाइट (25.2 प्रतिशत), बॉक्साइट (13.4 प्रतिशत), सोना (13.3 प्रतिशत), प्राकृतिक गैस (यू) (11.7 प्रतिशत) और कोयला (8.2 प्रतिशत)। ■

ईपीएफओ ने जनवरी, 2022 में कुल 15.29 लाख नए ग्राहक बनाए

गत 20 मार्च को जारी ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल डेटा के अनुसार ईपीएफओ ने जनवरी, 2022 के दौरान कुल 15.29 लाख नए ग्राहक बनाए। पेरोल डेटा की महीने-दर-महीने तुलना करने से दिसंबर, 2021 के पिछले महीने के दौरान शुद्ध परिवर्धन की तुलना में जनवरी, 2022 में 2.69 लाख ग्राहकों की वृद्धि का संकेत मिलता है।

महीने के दौरान बनाए गए कुल नए 15.29 लाख ग्राहकों में से लगभग 8.64 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के सामाजिक सुरक्षा दायरे के तहत पंजीकृत किया गया है।

पेरोल डेटा की आयु-वार तुलना से पता चलता है कि 18-25 वर्ष के आयु वर्ग ने जनवरी, 2022 के दौरान 6.90 लाख अतिरिक्त के साथ सबसे अधिक कुल नामांकन दर्ज किया है, जो कि महीने के दौरान कुल ग्राहकों की संख्या का लगभग 45.11 प्रतिशत है।

इसके बाद 29-35 वर्ष के आयु वर्ग द्वारा सकारात्मकता दर्शाते हुए लगभग 3.23 लाख नए नामांकन किए गए। यह इंगित करता है कि संगठित क्षेत्र के कार्यबल में रोजगार के इच्छुक बहुत से लोग पहली बार बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और उपार्जन क्षमता के मामले में किसी व्यक्ति की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण चरण का संकेत देते हैं। ■

रक्षा मंत्री ने 'फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटिग्रेशन परिसर' का किया उद्घाटन

इस इमारत में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को समर्थन दिया जाएगा

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 17 मार्च को बंगलुरू, कर्नाटक में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की एक प्रयोगशाला एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (एडीई) में सात मंजिला फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम (एफसीएस) इंटिग्रेशन फैसिलिटी का शुभारंभ किया। इस अत्याधुनिक परिसर को रिकॉर्ड 45 दिनों में बनाया गया है, जो परम्परागत, प्री-इंजीनियर्ड और प्रीकास्ट प्रणाली के साथ हाइब्रिड प्रौद्योगिकी से युक्त है। इस तकनीक को डीआरडीओ ने लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के साथ मिलकर विकसित किया था। डिजाइन और तकनीक समर्थन आईआईटी मद्रास और आईआईटी रुड़की की टीमों ने उपलब्ध कराया है।

यह एफसीएस फैसिलिटी एडीई, बंगलुरू द्वारा विकसित किए जा रहे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एवियॉनिक्स और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए एफसीएस के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) गतिविधियों के लिए समर्थन देगी।

रक्षा मंत्री ने कहा कि यह न सिर्फ देश के लिए, बल्कि दुनिया के लिए एक विशेष परियोजना है और नए भारत की नई ऊर्जा की प्रतीक है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह फैसिलिटी राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में एक लंबा सफर तय करेगी। उन्होंने कहा कि यह ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच प्रौद्योगिकी, प्रतिबद्धता, संस्थागत सहयोग है।

उन्होंने कहा कि परिसर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के पायलटों को सिम्युलेटर प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराएगा। श्री राजनाथ सिंह ने इसे परिसर के सबसे अहम कम्पोनेंट्स में एक बताया है। उन्होंने कहा कि सिम्युलेटर प्रशिक्षण से किसी प्रकार के नुकसान की संभावना के बिना गलतियों से सीखने का एक अवसर मिलता है।

हाइपब्रिड प्रौद्योगिकी के विकास के लिए डीआरडीओ और एलएंडटी की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इससे निर्माण प्रक्रिया की उत्पादकता बढ़ेगी; संसाधनों के उच्चतम उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा; वेस्टेज के चलते नुकसान कम होगा और परियोजनाओं के तेज कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। उन्होंने हाइब्रिड प्रौद्योगिकी को निर्माण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया और उम्मीद व्यक्त की कि भारत निर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक हो जाएगा।

श्री सिंह ने सशस्त्र बलों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों, छात्रों, किसानों और जनता के बेहतरी तथा एक खुशहाल व समृद्ध भविष्य की तलाश से जुड़ी कोशिशों में समर्थन देने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देने में डीआरडीओ द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका के लिए सराहना करते हुए कहा कि दुनिया में आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हालात बदल रहे हैं और बड़ी वैश्विक ताकतें आपस में जूझ रही हैं। हमारी रक्षा जरूरतें भी बढ़ गई हैं और सैन्य बलों का लगातार आधुनिकीकरण आज की जरूरत हो गई है। खुद को तैयार रखना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है और हम अपनी रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे यह तकनीक हो या उत्पाद, सेवाएं हों या फैसिलिटीज हों, उनका आधुनिकीकरण और तेज विकास वक्त की जरूरत है।

गौरतलब है कि एफसीएस फैसिलिटी 1.3 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बनी एक इमारत है। 45 दिन में निर्माण पूरा करने के साथ देश के निर्माण उद्योग के इतिहास में पहली बार हाइब्रिड निर्माण प्रौद्योगिकी के साथ एक स्थायी सात मंजिला भवन का निर्माण पूरा करने का एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया है। हाइब्रिड निर्माण प्रौद्योगिकी में ढांचे के खंभे और बीम स्टील की प्लेटों से बनाए गए हैं। खंभे खोखले स्टील ट्यूबलर सेक्शन के रूप में हैं। स्लैब आंशिक रूप से प्रीकास्ट हैं और इन सभी को साइट पर असेंबल किया गया है। ढांचे को एक रूप देने के लिए कंक्रीट बनाया गया है, जिससे हर शुष्क जोड़ को खत्म कर दिया गया है, जैसा प्रीकास्ट निर्माण के मामले में होता है।

उद्घाटन के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, रक्षा, आरएंडडी विभाग के सचिव और डीआरडीओ चेयरमैन डॉ. जी. सतीश रेड्डी और डीआरडीओ व राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे। ■

प्रधानमंत्री ने 'ऑपरेशन गंगा' में शामिल हितधारकों से वर्चुअल तौर पर मुलाकात की

गत 15 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'ऑपरेशन गंगा' में शामिल हितधारकों के साथ बातचीत की। ऑपरेशन गंगा के बल पर लगभग 23,000 भारतीय नागरिकों के साथ-साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला।

बातचीत के दौरान यूक्रेन, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी में भारतीय समुदाय और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने ऑपरेशन गंगा का हिस्सा बनने के अपने अनुभव, उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया और इस तरह के एक जटिल मानवीय ऑपरेशन में अपने योगदान पर संतोष और सम्मान की भावना व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के नेताओं, स्वयंसेवी समूहों, कंपनियों, व्यक्ति विशेष और सरकारी अधिकारियों की अत्यधिक सराहना की, जिन्होंने ऑपरेशन की सफलता के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने ऑपरेशन गंगा में शामिल सभी हितधारकों द्वारा प्रदर्शित देशभक्ति के उत्साह, सामुदायिक सेवा की भावना और टीम भावना की प्रशंसा की। श्री मोदी ने विशेष रूप से विभिन्न सामुदायिक संगठनों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी निःस्वार्थ सेवा भारतीय सभ्यता के मूल्यों का उदाहरण है जो वे विदेशी धरती पर भी अपनाते हैं।

संकट के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ अपनी व्यक्तिगत बातचीत को याद किया और सभी विदेशी सरकारों से प्राप्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।

विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा को सरकार द्वारा दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता को दोहराते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय संकट के दौरान अपने नागरिकों की सहायता के लिए हमेशा तत्परता से काम किया है। भारत ने 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के अपने सदियों पुराने दर्शन से प्रेरित होकर आपात स्थितियों के दौरान अन्य देशों के नागरिकों को भी मानवीय सहायता प्रदान की है। ■

प्रधानमंत्री ने एक साल में एक लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल करने पर 'जीईएम' की तारीफ की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च को महज एक साल में एक लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल करने पर सरकारी खरीद पोर्टल 'गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' (जीईएम) की तारीफ की। जीईएम को केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों की तरफ से की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए अगस्त, 2016 में शुरू किया गया था।

श्री मोदी ने एक ट्वीट में इस खरीद पोर्टल की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि यह जानकार खुशी हुई कि जीईएम इंडिया ने एक साल में ही एक लाख करोड़ रुपये मूल्य का ऑर्डर हासिल किया। यह पिछले वर्षों की तुलना में बहुत बड़ी वृद्धि है। उन्होंने कहा कि जीईएम मंच खास तौर पर एमएसएमई इकाइयों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि 57 फीसदी ऑर्डर मूल्य एमएसएमई क्षेत्र से ही आ रहा है। ■

बुद्धिजीवी समाज में राय बनाते हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च को अपने आवास पर देशभर के प्रमुख सिख बुद्धिजीवियों के शिष्टमंडल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने शिष्टमंडल के साथ किसान कल्याण, युवा सशक्तिकरण, नशा मुक्त समाज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौशल, रोजगार, प्रौद्योगिकी और पंजाब के आमूल विकास पर खुलकर बातचीत की।

श्री मोदी ने शिष्टमंडल से मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि बुद्धिजीवी समाज में राय बनाते हैं। उन्होंने शिष्टमंडल के सदस्यों से आग्रह किया कि वे जनता को जोड़ने, उन्हें शिक्षित करने तथा जनता को उचित जानकारी मिले, इस दिशा में वे काम करें। उन्होंने एकता की भावना पर बल दिया, जो हमारे देश की विशाल और सुंदर विविधता में प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करती है।

प्रधानमंत्री ने मातृभाषा में शिक्षा दिये जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मातृभाषा में उच्च शिक्षा को वास्तविकता बनाने के लिये भारतीय भाषाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

शिष्टमंडल ने निमंत्रण के लिये प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री इतने अनौपचारिक माहौल में उनके साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने सिख समुदाय के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गये विभिन्न उपायों की सराहना की। ■

भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 के अप्रैल-फरवरी में 21.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया

कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान 21.5 बिलियन डॉलर के बराबर के कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का सफलतापूर्वक निर्यात किया तथा यह चालू वित्त वर्ष के दौरान 23.71 बिलियन डॉलर के वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 25 मार्च को जारी एक बयान के अनुसार सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले के रूप में एपीडा द्वारा अभी तक 8.67 बिलियन डॉलर के चावल निर्यात लक्ष्य का 91 प्रतिशत अर्जित किया जा चुका है। भारत ने 8.62 बिलियन डॉलर के बराबर का चावल निर्यात किया है, जबकि अन्य अनाजों के निर्यात ने 847 मिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य की तुलना में 105 प्रतिशत की छलांग लगाई है।

गेहूं के निर्यात में वित्त वर्ष 2021-22 के अप्रैल-जनवरी के दौरान 1742 मिलियन डॉलर की भारी बढ़ोतरी देखी गई, जो वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि की तुलना में 387 प्रतिशत अधिक है जब इसने 358 मिलियन डॉलर के स्तर को छुआ था।

प्रसंस्कृत फल तथा सब्जियों का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 के अप्रैल-जनवरी के दौरान 11 प्रतिशत बढ़कर 1269 मिलियन डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल-जनवरी के दौरान यह आंकड़ा 1143

मिलियन डॉलर दर्ज किया गया था।

अनाज तैयारी तथा विविध प्रसंस्कृत मदों का निर्यात 2036 मिलियन डॉलर के बराबर का हुआ है जो चालू वित्त वर्ष के फरवरी तक 2102 मिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य का 89 प्रतिशत है, जबकि मांस, डेयरी तथा उत्पादों का निर्यात 3771 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया है जो फरवरी, 2022 तक 4205 मिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य का 82 प्रतिशत है। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

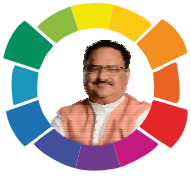

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'ऑपरेशन गंगा' (यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों के लिए सुरक्षित निकासी अभियान) में शामिल हितधारकों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 96वें सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा

नई दिल्ली में भारत–ऑस्ट्रेलिया दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया से वापस लायी गईं प्राचीन कलाकृतियों को देखते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2021-23
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

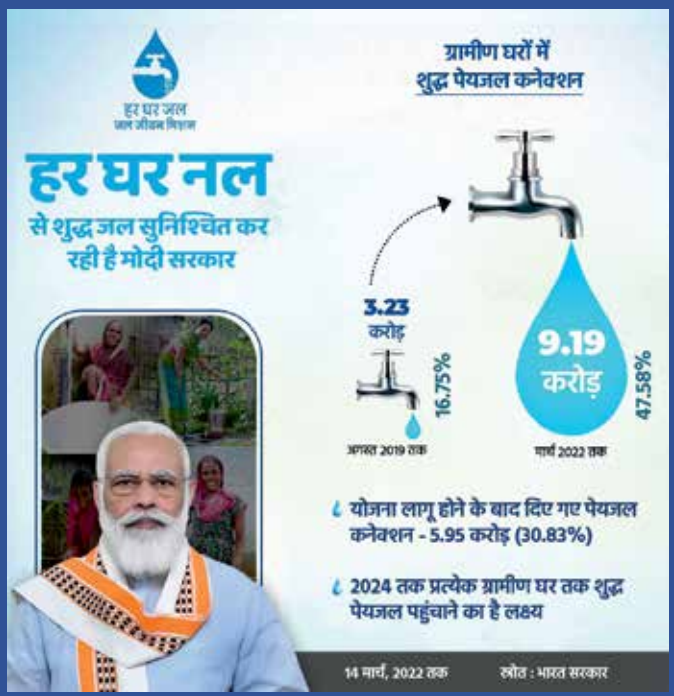

आवरण: अजय कुमार सिंह